

दैनिक

कारखाने का सफर



स्वच्छ सर्वेक्षण-2024-25

भोपाल "स्वच्छ शहर श्रेणी" में बजा

देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर मालती राय व निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायण ने प्राप्त किया पुरस्कार • भोपाल ने कचरा मुक्त शहर श्रेणी में प्राप्त की 7 स्टार रैंकिंग, स्वच्छतम राजधानी व वाटर+को खिताब रखा बरकरार • महापौर मालती राय ने भोपाल को मिले पुरस्कार को सफाई मित्रों एवं शहर के नागरिकों को किया समर्पित

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भोपाल ने देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गुरुवार को आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर व राज्यमंत्री तोखन साहू की उपस्थिति में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर मालती राय एवं निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायण को पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल ने कचरा मुक्त शहर श्रेणी में 7 स्टार रैंकिंग प्राप्त की और देश की स्वच्छतम राजधानी और वाटर + का खिताब भी बरकरार रखा। इस अवसर पर प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिभा बागरी, केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कातकीथला, निगम के अपर आयुक्त देवेन्द्र सिंह चौहान, महापौर परिषद के सदस्य आर.के.सिंह बघेल व रविन्द्र यति, प्रभारी मुख्य अभियंता उदित गर्ग, प्रभारी उपायुक्त चंचलेश गिरहेर आदि भी मौजूद थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण-2024-25 की "स्वच्छ शहर श्रेणी" में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भोपाल को देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है साथ ही कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में 7 स्टार रैंकिंग प्रदान की गई है। भोपाल ने देश की

सबसे स्वच्छतम राजधानी होने के साथ ही वाटर + सिटी का गौरव भी बरकरार रखा है। रिड्यूज, रीयूज, रिसायकल थीम पर सम्पन्न हुए स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में भोपाल नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में निर्धारित 10 हजार अंकों में से 09 हजार 567 अंक तथा सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित 02 हजार 500 अंकों में से पूरे 02 हजार 500 अंक प्राप्त किए। इस प्रकार 12 हजार 500 अंकों में से भोपाल शहर ने 12 हजार 67 अंक अर्जित करते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा तथा प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उपरोक्त अंकों को प्राप्त करने हेतु नगर निगम, भोपाल द्वारा सम्पूर्ण शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण के निर्धारित मापदण्डों अनुसार स्वच्छता की गतिविधियां प्रभावी ढंग से संचालित की साथ ही कचरे का उत्सर्जन कम करने की दिशा में भी कार्य करते हुए अप्रोसरचना एवं प्रसंस्करण पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए गत वर्ष में कचरा प्रबंधन के संसाधनों में वृद्धि की गई और कचरा प्रबंधन हेतु प्रभावी कार्यवाही व नवाचार भी किए। स्वच्छता की गतिविधियों में महापौर मालती राय एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा निरंतर स्वयं भी सहभागिता दर्ज कराई गई और आमजन को भी स्वच्छता की गतिविधियों में सक्रिय तौर पर सहभागिता करने हेतु प्रेरित किया और स्वच्छता संबंधी सभी कार्यों की सूक्ष्मता से मॉनीटरिंग की गई। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायण ने प्रतिदिन निरंतरता के साथ साफ-सफाई व्यवस्था की निगरानी की और इसे बेहतर एवं व्यापक स्तर पर सुनिश्चित कराने हेतु

आवश्यक दिशा निर्देश समझ में तथा वी0सी0 के माध्यम से दिए। निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमलेश विशेकर सफाई मित्रों ने अपने शहर भोपाल को देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बनाने में अपनी तत्परता एवं कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है साथ ही स्वच्छता एम्बेसडर व एन.जी.ओ ने भी शहर में साफ-सफाई सुनिश्चित कराने व आमजन को स्वच्छता हेतु प्रेरित करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। शहर के नागरिकों ने भी निगम द्वारा की जाने वाली स्वच्छता की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई और निगम के स्वच्छता संबंधी प्रत्येक कार्य में सहयोग भी दिया। महापौर श्रीमती मालती राय देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छतम राजधानी व गाबेंज प्री सिटी में 7 स्टार रैंकिंग प्राप्त होने पर भोपाल शहर के नागरिकों और निगम के सफाई मित्रों सहित अन्य को बधाई प्रेषित करते हुए इस गौरव को प्राप्त होने का पूरा श्रेय निगम के सफाई मित्रों व नागरिकों को दिया एवं उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत किये गये कार्य

नगर निगम द्वारा कचरा एकत्रीकरण की प्रक्रिया के समानांतर अपशिष्ट प्रसंस्करण की व्यवस्था को और अधिक बेहतर ढंग से संचालित करते हुए शहर से निकलने वाले कचरे के प्रकारों और उनकी मात्रा का आकलन करते हुए टेलर कट मॉडल के आधार पर कचरे के निष्पादन की व्यवस्था की। निगम द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्लांटों को वर्गीकृत करते हुए

सेंट्राइज्ड और डिसेंट्राइज्ड प्लांट स्थापित करने का कार्य किया। सेंट्राइज्ड प्लांट के रूप में एन.टी.पी.सी. द्वारा 400 टन प्रतिदिन क्षमता का टेरिफाईड चारकोल प्लांट एवं 400 टन गैले कचरे से बायो सी.एन.जी प्रोसेसिंग प्लांट शामिल है। (1) 05 स्थानों पर नवीन गारबेज ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण। (2) 125 नवीन CNG डोर.टू.डोर वाहनों का क्रय. नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण की क्षमता में वृद्धि एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत कचरा एकत्रीकरण हेतु 125 नग सीएनजी वाहन UNIDO की सहायता से क्रय किये गये हैं। इस तरह अब नगर निगम में कुल 700 डोर.टू.डोर वाहन में से 250 सीएनजी डोर.टू.डोर वाहन हो गये हैं। (3) 06 मेकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग वाहन शहर की सड़कों की समुचित साफ-सफाई व धूल से मुक्ति हेतु 06 नवीन मेकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग वाहन क्रय किये गये हैं। अब नगर निगम भोपाल में मेकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग वाहन की संख्या 04 से बढ़कर 10 हो गई है। (4) 06 नग हुकलोर वाहन- नगर निगम, भोपाल द्वारा 06 नग हुकलोर वाहन क्रय किये गये हैं। इनके माध्यम से पृथक-पृथक कचरा ट्रांसफर स्टेशन से लैंडफिल साइट ले जाया जा रहा है। (5) प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, आदमपुर (1) प्लांट की क्षमता 5 टन प्रतिदिन है और पीपीपी मोड पर संचालित इस प्लांट में प्लास्टिक का संग्रहण कर निष्पादन करते हुए प्लास्टिक शीट, बोर्ड आदि तैयार किये जायगा।

(6) C&D प्रोसेसिंग प्लांट- नगर निगम, भोपाल द्वारा 100 टन प्रति दिन क्षमता का C&D प्रोसेसिंग प्लांट, वीजीएफ मोड में लागूया गया है इस प्लांट द्वारा लगभग 24 हजार पेपर ब्लॉक एवं 100000 ब्रिक्स प्रति महीने बनाई जा रही है। (7) भानपुर रेमेडीएटेड साईट 40 वर्ष पुरानी भानपुर डम्प साईट को वैज्ञानिक पद्धति से रेमेडीएटेड किया गया है लगभग 7.23 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपचार किया गया और 21 एकड़ भूमि को रिक्लेम एवं 16 एकड़ में हरित क्षेत्र विकसित किया गया। (8) फूलों एवं निर्माल्य से बहुउपयोगी उत्पाद हेतु रिसायकल यूनिट - भोपाल शहर के प्रत्येक वार्डों के मंदिरों से उत्पन्न होने वाले फूल अपशिष्ट के निष्पादन हेतु इकाई की स्थापना की गयी है। जिसमें अगरबत्ती फूलों से गुलाल जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं। (9) थर्माकोल रिसाइकल इकाई - नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पी.पी.पी मोड पर 01 टन प्रतिदिन क्षमता की विकेंद्रीकृत थर्माकोल रिसाइकल इकाई की स्थापना दानापानी गाबेंज ट्रांसफर स्टेशन में की गई है जिसमें पैकेजिंग थर्माकोल को रिसायकल कर निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। (10) कोकोनट प्लांट - शहर से निकलने वाले नारियल के कचरे के उचित निष्पादन हेतु नारियल वेस्ट प्लांट।

समाचार संपादक की कलम से
-राहुल कौशिक

दुनिया में कितना पैसा है और यह कहाँ-कहाँ है ?

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

HOW MUCH MONEY IS THERE IN THE WORLD?
\$583 trillion

आज की तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में यह जानना अत्यंत रोचक है कि दुनिया में कुल मिलाकर कितना पैसा है और यह किन देशों के पास केंद्रित है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि दुनिया का सारा पैसा बराबर बांटा जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा ?

कुल पैसा कितना है ?

विश्व की कुल मुद्रा आपूर्ति (Money Supply) को आर्थिक शब्दों में M2 कहा जाता है, जिसमें नकद, बैंक जमा, और लिक्विड सेविंग्स शामिल होते हैं। वर्ष 2025 तक के अनुमानों के अनुसार, दुनिया में कुल 583 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर पैसा मौजूद है। हालांकि, अलग-अलग देशों में पैसा बराबर बांटा जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा ?

अलग-अलग देशों में पैसा कितना है ?

आइए जानें कि कौन-कौन से देश इस वैश्विक संपदा में सबसे आगे हैं:

देश	अनुमानित मुद्रा (M2) - US डॉलर में
चीन	\$44 ट्रिलियन
यूरोपीय संघ	\$16 ट्रिलियन
जापान	\$10 ट्रिलियन
संयुक्त राज्य अमेरिका	\$21 ट्रिलियन (लगभग)
भारत	\$0.77 ट्रिलियन (₹64 लाख करोड़)
ब्राजील	\$1 ट्रिलियन

कनाडा \$1.8 ट्रिलियन-

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि दुनिया के चार बड़े आर्थिक ब्लॉक — चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान — के पास कुल पैसा का बड़ा हिस्सा है। वहीं भारत जैसे देश, जो जनसंख्या में अग्रणी है, अब भी आर्थिक संसाधनों के मामले में काफी पीछे है।

क्या यह असमानता चिंता का विषय है ?

जी हाँ। आज विश्व की 10% आबादी के पास दुनिया की 80% संपत्ति है, जबकि 90% लोग शेष 20% पर निर्भर हैं। यह आर्थिक विषमता न केवल सामाजिक असंतुलन को जन्म देती है, बल्कि वैश्विक विकास को भी सीमित करती है।

भारत का क्या स्थान है ?

भारत में कुल M2 मुद्रा आपूर्ति लगभग 64 लाख करोड़ है, जो दुनिया की तुलना में बहुत कम है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और अगले कुछ वर्षों में भारत शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है।

निष्कर्ष- दुनिया में पैसा भरपूर है, लेकिन इसका वितरण बेहद असमान है। चीन, अमेरिका और यूरोप के पास अधिकांश संपत्ति है, जबकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों के पास सीमित संसाधन हैं। इस असमानता को कम करने के लिए वैश्विक नीतियों, शिक्षा, निवेश और पारदर्शिता की आवश्यकता है।

अहमदाबाद फ्लाइट हादसा: पूरी जांच से पहले कैप्टन को दोष देना बिल्कुल गलत

दैनिक कारखाने का सफर। एजेंसी नई दिल्ली

भारतीय पायलट महासंघ (एफआईपी) ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) में प्रकाशित एक लेख की कड़ी आलोचना की है, जिसमें अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे के लिए कैप्टन को गलत तरीके से दोषी ठहराने का आरोप लगाया गया है। डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह दुर्घटना विमान में ईंधन नियंत्रण सिस्टम की गति से जुड़ी पायलट

की गलती का परिणाम थी। एफआईपी प्रमुख सीएस रेखावा ने अमेरिकी मीडिया संस्थान की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले हफ्ते जारी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए पायलटों को दोषी नहीं ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि पायलट की गलती के कारण ईंधन नियंत्रण सिस्टम बंद हो गया था। मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख की निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि यह पायलट की गलती थी।

भेल कारखाने में पीएनजी पाइप लाइन बिछेगी, ईडी ने किया पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि पूजन

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

बीएचईएल, भोपाल में गुरुवार को प्रदीप कुमार उपाध्याय, महाप्रबंधक एवं प्रमुख, बीएचईएल, भोपाल ने पाइप नेचुरल गैस (PNG) पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर डी. एस. दुर्गा, क्षेत्रीय प्रमुख, मेसर्स थिंक गैस जो इस परियोजना के क्रियान्वयन



एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अवसर पर विपुल अग्रवाल, महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंध), विकास खरे, महाप्रबंधक (ईएम), जी. पी. बघेल, महाप्रबंधक (गुणता), आशीष औरंगाबादकर, महाप्रबंधक (WEX & MOD), सभी महाप्रबंधक, जी अस्थाना, सहायक कमांडेंट (सीआईएसएफ) सहित अन्य उत्पाद प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

PNG पाइपलाइन बिछाने का उद्देश्य संयंत्र में वर्तमान में उपयोग हो रहे एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) और फर्नेस ऑयल के स्थान पर स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक कुशल ईंधन के विकल्प अपनाना है। इस पहल से लगभग 4000 मीट्रिक टन CO उत्सर्जन में वार्षिक कमी आएगी जो कि प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख पेड़ लगाने के बराबर है।

यह परियोजना पर्यावरण स्थिरता के प्रति बीएचईएल की प्रतिबद्धता को और भी सुदृढ़ करती है और 2047 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान देने में बीएचईएल की पहल को प्रदर्शित करती है।

हर्षवर्धन काम्पलेक्स स्थित माता मंदिर कार्यालय में भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान हासिल करने पर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने स्वच्छता मित्रों संग मनाई खुशियां



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

स्वच्छ सर्वेक्षण अवॉर्ड 2024-25 में भोपाल ने देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त कर एक बार फिर स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान स्थापित की है। यह उपलब्धि भोपाल नगर निगम, समर्पित स्वच्छता मित्रों एवं समस्त नागरिकों के सामूहिक प्रयास और समर्पण का प्रतिफल है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर भोपाल नगर निगम अध्यक्ष माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी ने स्वच्छता मित्रों को मिठाई खिलाकर एवं पुष्पवर्षा कर सम्मानित किया। पुष्पवर्षा के दौरान उपयोग किए गए फूल भी स्वच्छता मित्रों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। जिन्हे पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, उन फूलों को नगर निगम अध्यक्ष द्वारा स्वयं झाड़ू लगाकर एकत्रित कर खाद निर्माण हेतु पुनः उपयोग में लिया जाएगा। इस पहल के माध्यम से स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

दैनिक कारखाने का सफर अखबार का संपादकीय कार्यालय

गोबिंद टॉवर, क्वालिटी रेस्टोरेंट के पास, एसबी स्टूडियो के ऊपर पिपलानी पेट्रोल पंप के पास, सोनागिरी चौराहा रायसेन रोड भोपाल। मोबाइल नंबर: 9826035849, 9425006706

साइकिल पाकर रिवल उठे विद्यार्थियों के चेहरे



दैनिक कारखाने का सफर। पठा

ग्राम पंचायत पठा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्यप्रदेश शासन की महती योजना निशुल्क साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
कैचमेंट शालाओं के छात्र छात्राओं जो पाठ्य स्कूल में अध्ययन हेतु आते हैं उन्हें निशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है।
यह समारोह श्री ललित अहिरवार उपाध्यक्ष जनपद

पंचायत टीकमगढ़ के मुख्य आतिथ्य एम सरपंच ग्राम पंचायत पठा श्री जयमराय राय के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने की। इस मौके पर संस्था के प्राचार्य श्री सी. एल. अहिरवार, समस्त स्कूल स्टाफ के साथ-साथ छात्र छात्राओं के अभिभावक उपस्थित रहे। साइकिल मिलते ही छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम का संचालन श्री अरविंद कुमार साहू के द्वारा किया गया।

श्रीमद् भागवत कथा समापन में शामिल होकर विधायक प्रतिनिधि ने लिया आशीर्वाद



दैनिक कारखाने का सफर। सारंगपुर
सारंगपुर स्थानीय राजपूत (सोनगरा) परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के समापन में सारंगपुर

विधायक प्रतिनिधि पृथ्वीराज टेटवाल ने सम्मिलित होकर कथा वाचक का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विकास दीक्षित, महामंत्री सुदर्शन सोनी, दीपक चोहान एवं ग्रामीण जन सम्मिलित हुए।

ब्रह्मानंद यादव के निधन पर राज्यमंत्री टेटवाल ने अर्पित की श्रद्धांजलि

दैनिक कारखाने का सफर। सारंगपुर

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के ससुरजी एवं विद्या भारती महाकौशल प्रांत के पूर्व प्रांत संगठन मंत्री ब्रह्मानंद यादव के निधन उपरांत रीवा स्थित निज-निवास पर पहुंचकर सारंगपुर विधायक एवं राज्यमंत्री गौतम टेटवाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक-संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। श्रीटेटवाल ने कहा कि स्व. श्री ब्रह्मानंद यादवजी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अनुषंगिक संगठनों में कार्य करते हुए मां भारती की सेवा में समर्पित किया। इस दुःखद की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने शीर्षकों में स्थान दें और परिवार को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।



स्पेन में दुनिया की बड़ी कॉटन-कंपनी से सीएम की चर्चा: इंडिटेक्स को सप्लाई चेन एंकर में भागीदार बनाने का प्रस्ताव

दैनिक कारखाने का सफर। सारंगपुर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पेन यात्रा के दूसरे दिन गैलिसिया स्थित इंडिटेक्स मुख्यालय में कंपनी के प्रबंधन के साथ व्यापारिक चर्चा की। इस दिन, सीएम का ध्यान वैश्विक कपड़ा और फैशन क्षेत्र के दिग्गजों से मध्य प्रदेश में निवेश पर केंद्रित रहा। उन्होंने इंडिटेक्स को पीएम मित्रा पार्क में सप्लाई चेन एंकर के रूप में भागीदार बनने का प्रस्ताव दिया।
साथ ही, एक ऑर्गेनिक कॉटन ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म और इंग्लैंड की सॉर्टिफाइड एमएसएमई के साथ वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का सुझाव दिया। बता दें कि इंडिटेक्स दुनिया की बड़ी फैशन रिटेल कंपनी है, जिसके जारा, मैसिमो दुत्ति, बेरशाका, बुल एंड बीयर जैसे प्रसिद्ध ब्रांड हैं। कंपनी का मुख्यालय गैलिसिया के आतेइसो में है। सीएम ने मध्य प्रदेश को "हरित, लागत-प्रतिस्पर्धी और ट्रेसिबल उत्पादन हब" के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इंडिटेक्स जैसे प्रसिद्ध ब्रांड की मौजूदगी से राज्य में आर्थिक विकास होगा और रोजगार बढ़ेगा। साथ ही, हरित उत्पादन को गति मिलेगी। सीएम ने मद्रास को देश में कच्चा कपास उत्पादन करने



वाले राज्यों में शीर्ष पर बताया और कहा कि यहां सालाना लगभग 18 लाख बेल्ट्स (3 लाख मीट्रिक टन) का उत्पादन होता है। प्रदेश में 15 से अधिक टेक्सटाइल क्लस्टर हैं, जिनमें इंदौर, मंदसौर, बुरहानपुर, उज्जैन, नीमच के क्लस्टर बेहतरीन उत्पादन कर रहे हैं।

उन्होंने धार जिले में भारत सरकार की पीएम मित्रा योजना के तहत बन रहे टेक्सटाइल मेगा पार्क को इंडिटेक्स जैसे विश्व स्तरीय ब्रांड के लिए सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग का आदर्श केंद्र बताया। सीएम ने इस पार्क में गारमेंटिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।

एट्रोसिटी एक्ट के पालन में संवेदनशीलता जरूर, रेलवे पुलिस द्वारा एक दिनी सेमिनार का आयोजन

दैनिक कारखाने का सफर। इंदौर

इंदौर में गुरुवार को रेलवे पुलिस द्वारा 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एक्ट के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता' विषय और रेलवे जीआरपी की भूमिका, सुरक्षा और पंचनामा की कानूनी महत्व को लेकर एक दिनी सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें जीआरपी के प्रशिक्षणार्थियों को एक्ट की सारी प्रक्रिया और महत्व को लेकर क्या विधिवत कार्यवाही होनी चाहिए उसे लेकर ट्रेनिंग दी गई। सेमिनार में एडवोकेट (सुप्रीम कोर्ट) तनुज दीक्षित ने एट्रोसिटी कानून के साथ रेलवे पुलिस की भूमिका, जर्नी की प्रक्रिया एवं सावधानियां, प्रक्रियागत जटिलताएं, पंचनामा और उसके महत्व, चालान आदि गंभीर विषयों पर जीआरपी की जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चूँकि रेल पुलिस की एक विशेष यूनिट है, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अंतरराज्यीय समन्वय के साथ और



अपराधियों को पकड़ना होता है। इसके लिए सभी की ट्रेनिंग कर पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया। साथ ही सुधार मजबूती से हो इसे लेकर अधिक जानकारी साथ तकनीकी दक्षता, संवेदनशीलता और जवाबदेही का संतुलित समावेश भी सिखाया। सेमिनार में जीआरपी एसपी संतोष कोरी, डीएसपी ज्योति शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।

इंदौर आठवीं बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, मंत्री, महापौर और आयुक्त ने लिया पुरस्कार

दैनिक कारखाने का सफर। इंदौर

गुरुवार को दिल्ली में घोषित हुए स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 के नतीजों में इंदौर ने एक बार फिर देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। यह लगातार आठवीं बार है, जब इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को सम्मानित किया। इस बार इंदौर को "सुपर लीग" में भी शामिल किया गया है, जिसमें देश के उन 23 शहरों को जगह दी गई है जो अब तक के सर्वे में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रह चुके हैं (सम्मान समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्पामित्र भार्गव और निगम आयुक्त भी मौजूद थे। इंदौर महापौर पुष्पामित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर फिर सिरमौर है। इस बार भारत सरकार ने इंदौर और इंदौर जैसे शहरों को अलग लीग में रखा था और उसके अलावा के शहरों की रैंकिंग की थी। इस लीग में हम देश के अन्य शहरों से पहले भी सबसे ऊपर थे। इस लीग में आकर भी इंदौर का परिणाम सिरमौर का है। देशभर के शहरों के लिए स्वच्छता का मॉडल बन चुका इंदौर नंबर 1 की प्रतिष्ठा से बहुत आगे निकल चुका है। अब इंदौर मार्गदर्शक की भूमिका में है और अन्य शहरों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाएगा। महापौर पुष्पामित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर अब स्वच्छता का गुरु है। इसके पीछे मेहनत और ताकत इंदौर की जनता और सफाई मित्र हैं। यह सिलसिला आगे हम कायम रखेंगे। यहां तक पहुंचने में हमारे सफाई मित्र और वाहन चालकों की अथक मेहनत है। इसलिए कल यानी शुक्रवार सुबह जब सफाई मित्र आपके घर आए तो उनका स्वागत करें। निगमायुक्त

शिवम वर्मा ने कहा हम आगे भी इसी जोश और जिम्मेदारी से इंदौर को स्वच्छ बनाए रखेंगे। यह सम्मान हम सबकी साझा उपलब्धि है। अब हम दूसरे शहरों को ट्रेड करेंगे। शहरवासी और निगम की टीम साथ मिलकर काम करती रहेगी तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। इंदौर हमेशा नंबर वन रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण में वर्ष 2017 से इंदौर पहले नंबर पर आ रहा है। इंदौर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि दूसरे शहर जब कुछ करने का सोचते हैं, तब तक इंदौर वह काम कर चुका होता है। यह बात स्वच्छता को लेकर भी सही साबित हुई है। इंदौर के जनभागीदारी मॉडल की देशभर में तारीफ होती है। नवाचारों की सोरीज, आपसी समन्वय और कुछ नया करने का जज्बा हमें दूसरे शहरों से आगे रखता है। आज जब दूसरे शहर पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए जिद्दीजद्द में लगे हैं। इंदौर लगातार 8 वर्ष अक्वल रहकर खास पायदान पर पहुंच चुका है। सुपर लीग में शामिल शहरों को सिर्फ अपने आपको ही स्वच्छ नहीं रखना है बल्कि उस शहर की सफाई व्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें 17 जुलाई को सौंपी गई। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम घोषित होने के कार्यक्रम के साक्षी शहरवासी भी बन सकें, इसके लिए निगम मुख्यालय पर बड़ी स्क्रीन पर कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड की सबसे अहम कैटेगरी में मद्रास की राजधानी भोपाल को अवॉर्ड मिलना तय हो गया है। इसी तरह देवास नगर निगम को भी प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा और शरांगज को भी अवॉर्ड के लिए चिह्नित किया गया है। इन सभी शहरों को उनकी संबंधित कैटेगरी में यह अवॉर्ड दिया जाएगा।



शासकीय प्राइमरी स्कूल बीडीए एवं शासकीय मिडल स्कूल अमरावत खुर्द के 200 बच्चों को वितरण किया बैग



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

शासकीय प्राइमरी स्कूल बीडीए कॉलोनी एवं अमरावत खुर्द में स्कूली बच्चों को मध्य प्रदेश शासन में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी ने स्कूल के सभी बच्चों को बैग वितरित किए

आयोजक अतुल कुमार अंजान ने बताया कि माननीय ,मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों से बीडीए एवं अमरावत खुर्द में स्थित स्कूल में बच्चों को विभिन्न तरह के सामग्री उपलब्ध कराई जाती है एवं मंत्री जी ने बच्चों को उत्साह वर्धन उद्बोधन किया इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर

मनीष शर्मा जी संकुल प्राचार्य श्री मति स्मिता मेश्राम जी,ACS अर्पिता सिंह चौहान,डॉक्टर करण सिंह स्कूल प्राचार्य श्री मति शोभना उपाध्याय जी बिधानसभा प्रभारी श्री गणेश राम नगर जी, मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र धोटे क्षेत्रीय वार्ड क्रमांक 60 पार्षद बी शक्ति राव जी ,अवधपुरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष किशन बंजारे जी

,61 वार्ड की पार्षद मधु शिवनानी जी, की उपस्थित में कार्यक्रम संपन्न किया गया जिसमें मुख्य रूप से अवधपुरी के मंडल महा मंत्री संजय शिवनानी जी, अंकित मेश्राम जी, मंत्री श्री रुपेश पाटिल ,श्री मती खुशबू सिंह जी , विधायक प्रतिनिधि आनंद पाठक जी, पुष्पराज रघुवंशी जी, नवीन गुर्जर जी, समरजीत

यादव जी, तेजस्वी धोटे,विनोद चौकसे जी, मलखान सिंह जी , महासंघ के सचिव श्री RS नागर जी श्री, मुन्नालाल रैकवार जी, श्री जे.पी.पटेल जी कमलेश परमार जी, श्री जसवंत सिंह जी श्री भास्कर राव जी,एवं सभी स्कूल एवं संजीवनी के स्टाफ स्थानीय लोग कार्यक्रम में बह चढ़कर भाग लिया

अमेरिका में हुए पुलिस एवं अग्निशमन खेल प्रतियोगिता में सीआईएसएफ ने जीते 64 पदक



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई भेल भोपाल के वरिष्ठ कमांडेंट श्री शिवरतन सिंह मीणा ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में कुल 64 पदक जीत कर देश का गौरव बढ़ाया है। विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन

है जहां दुनिया भर के पुलिस और अग्निशमन कर्मी विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस वर्ष, 70 से अधिक देशों के 1000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। औद्योगिक सुरक्षा बल टीम ने 6 स्पर्धाओं में भाग लेकर प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और अदम्य साहस, शक्ति और टीम वर्क का परिचय दिया। उनकी सफलता ने भारत को 560 पदकों के साथ समग्र पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहने में मदद की।

भारत के गौरव शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा सफलता पर उनका छाया चित्र लेकर मंडल का 12 वा जत्था अमरनाथ रवाना हुआ

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

ओम शिव शक्ति सेवा मंडल भोपाल के सचिव रिंकू भट्टेजा ने बताया कि 85 श्रद्धालुओं का 12 वा जत्था मण्डल अध्यक्ष राज कुमार शर्मा के नेतृत्व में भारत के गौरव अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की छायाचित्र लेकर अमरनाथ रवाना हुआ। इस जत्थे में 26 महिलाएं शामिल हैं। रिंकू भट्टेजा ने आगे बताया कि 3 जुलाई से अब तक 14 दिनों में 2,47,000 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। 17 जुलाई को अमरनाथ में मूसलाधार वर्षा होने के कारण पहलगाय एवं बालटाल दोनों मार्गों से यात्रा स्थगित कर दी गई है।



चित्रांश सुर-सरिता ग्रुप द्वारा विगत दिवस "सावन-महोत्सव" का आयोजन



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

चित्रांश सुर-सरिता ग्रुप द्वारा विगत दिवस "सावन-महोत्सव" का आयोजन भोपाल के होटल आदित्य रेसीडेंसी में सम्पन्न हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने सावन के एकल व युगल गीत प्रस्तुत किये। कार्यक्रम में सर्वश्री डीके-साधना श्रीवास्तव,

रमेश-रीता श्रीवास्तव, अभय-वंदना प्रधान, डॉ. डीके-आशा श्रीवास्तव, योगेंद्र-सिंधु श्रीवास्तव, अरविंद सिन्हा, धर्मेन्द्र सक्सेना, मधुकर निगम, आर.एस.सक्सेना, एस.के.-शोभा सक्सेना, आरती सक्सेना, विपिन श्रीवास्तव, डा.धर्मेन्द्र-डा. कीर्ति खरे, श्रद्धा वर्मा, के.एन.श्रीवास्तव, एस.के.श्रीवास्तव, सुधीर-अनु श्रीवास्तव ने अपनी बेहतर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सभी हरे परिधान में उपस्थित हुए।



भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष केवल मिश्रा ने निर्मम हत्या मामले में थाना पिपलानी के थाना प्रभारी चंद्रिका यादव से मुलाकात की

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

पिछले दिनों हुई अंबेडकर पार्क बरखेड़ा में श्याम मोरे की निर्मम हत्या करने वाला अपराधी फैजान बैग जो जोकि थाना पिपलानी के पीछे तरफ में जो मस्जिद है उन झुगियों में रहता है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष केवल मिश्रा थाना पिपलानी के थाना प्रभारी चंद्रिका यादव से मुलाकात की और उनको बताया की जो बरखेड़ा में मर्डर करने वाला अपराधी है वह इसी थाने के अंतर्गत रहता है और उनसे निवेदन कर की इसकी बैकग्राउंड जांच करके इनके परिवार में कितने अपराधी पंजीबद्ध हैं। अगर पंजीबद्ध है तो, उनकी झुगियों को यहां से हटाया जाए मुलाकात में रमेश भारती, राजू यादव, नरेंद्र माली, सूरज खरे, लोकेश प्रजापति भी साथ में थे।



राहुल गांधी खुद जमानत पर घूम रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा से डरते हैं, मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा हमला

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर राहुल गांधी द्वारा दिए बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, "राहुल गांधी, हेमंत बिस्वा शर्मा से भयभीत हैं। शर्मा और कांग्रेस ने असम में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा।" सारंग ने राहुल पर हमला जारी रखते हुए कहा, "राहुल गांधी खुद जमानत पर घूम रहे हैं। पूरा नेहरू परिवार करोड़ों रूपए खा चुका है। अपने ऐशोआराम के लिए ट्रस्ट का पैसा डकार गए हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं"



कांग्रेस को नकल से पहले अकल की जरूरत है : मंत्री सारंग कांग्रेस द्वारा आयोजित विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को लेकर मंत्री सारंग ने कहा, "कांग्रेस

को पहले खुद प्रशिक्षित होना चाहिए। वो बीजेपी की नकल करने में जुटे हैं, लेकिन खुद ही अनुशासनहीन और अप्रशिक्षित हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, "कांग्रेस अनुशासनहीनता की परकाष्ठा है। उनके नेता सिर्फ अत्यवस्था और भ्रम फैलाने में निपुण हैं।" नेहरू परिवार का इतिहास ही भ्रष्टाचार का रहा है : सारंग उन्होंने कहा, "जब से नेहरू परिवार ने देश में शासन किया है, तब से भ्रष्टाचार हुआ है। जनता को गुमराह करने वाले बयानों से राहुल गांधी बाज नहीं आ रहे। बिना तथ्य और मुद्दे के बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता।"

भेल कर्मचारी ठेका श्रमिक संयुक्त मोर्चा ने मंत्री कृष्णा गौर को ज्ञापन सौंपा

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

भेल कर्मचारी ठेका श्रमिक संयुक्त मोर्चा की संरक्षक एवं मध्य प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर से गुरुवार को मंत्रालय वल्लभ भवन मंत्री कक्ष में मोर्चा के अध्यक्ष बारेलाल अहिरवार के नेतृत्व में ज्ञापन सोपा। मोर्चा अध्यक्ष बारेलाल अहिरवार द्वारा बताया कि भेल प्रबंधक द्वारा की जा रही सीधी भर्ती में ठेका श्रमिकों को नियमित निर्धारित कर प्राथमिक दिलाई जाए एवं वर्तमान समय की महंगाई को देखते हुए सम्मान वेतन वृद्धि कराई जाए ज्ञापन सोपा। मोर्चा महामंत्री सुभाष श्रीवास्तव उपाध्यक्ष अजय मिश्रा, मंत्री प्रकाश यादव शामिल थे। मंत्री कृष्णा गौर ने आश्वासन दिलाया कि ठेका श्रमिकों को न्याय दिलाया जाएगा।



मगर बात पहुंची कहां!



भारत का जोर इस पर है कि सरहद से जुड़े मुद्दों को पहले हल किया जाए, तभी संबंध सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस बीच भारत की निगाह में व्यापार संबंधी चीन के 'प्रतिबंधात्मक कदम' भी संबंध में रोड़ा बन गए हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर शंभू सिंह सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने चीन गए हैं, तो वहां उनकी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो बताया गया, उससे यही संकेत मिला कि फिलहाल दोनों देश बातचीत जारी रहने को ही एक उपलब्धि मान रहे हैं। दोनों देश गुजरे एक वर्ष में संबंध सुधार की दिशा में कुछ प्रगति का उल्लेख करते हुए संबंध और बेहतर करने इच्छा जता रहे हैं, संभवतः इसे भी एक कायमाबू माना जा सकता है। वरना, कड़वी हकीकत यह है कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने रुख को दोहराया भर है। भारत का मुख्य जोर इस पर है कि सरहद से जुड़े मुद्दों को पहले हल किया जाए, तभी संबंध सुधार की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ेगी। इस बीच भारत की निगाह में व्यापार संबंधी चीन के 'प्रतिबंधात्मक कदम' भी संबंध सुधार में बाधक बन गए हैं। जब ये बात जयशंकर ने वांग के सामने कही, तो साफ तौर पर उनका इशारा चीन द्वारा रेयर अर्थ खनिजों के निर्यात पर रोक तथा अपने तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा वापस लेने जैसे फैसलों की तरफ था। मगर भारत की बातों का कोई असर चीन पर होता नहीं दिखता है। उसकी तरफ से हर बार यही दोहराया जाता है कि भारत और चीन दोनों पूर्वी सभ्यता और उपरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों देशों के रिश्तों का सार सद्भावपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनाने और पारस्परिक सफलता की राह पर चलने में है। इन अमूर्त बातों का अर्थ संभवतः चीन की यह इच्छा है कि भारत उसकी विश्व दृष्टि एवं वैश्विक पहल से समन्वय बनाए। अन्यथा चीन की दिलचस्पी भारत से टकराव को नियंत्रित रखने तक सीमित रहेगी। गौरतलब है कि लद्दाख में सीमा पर दोनों देशों की फौजों के बीच आमने-सामने तैनाती की स्थिति बदली है, मगर अपनी- अपनी तरफ सेनाओं का जमाव जारी है। वार्ता के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने सीमा पर तनाव घटाने- यानी फौज वापसी पर जोर दिया। मगर चीन ने इस पर कोई सकारात्मक जवाब दिया, इसका कोई संकेत नहीं है।

ये नजरिया हानिकारक है!



यह फैसला इस समझ को ठेगा दिखाता है कि प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या का स्वरूप विश्वव्यापी है। उत्सर्जन चाहे कहीं भी हो, उसका प्रभाव दूर तक जाता है। इस रूप में यह निर्णय पर्यावरण की चिंता को ही ठेगा दिखाता है। खबर सचमुच परेशान करने वाली है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के ज्यादातर ताप बिजली संयंत्रों को फ्यूल गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम लगाने से छूट दे दी है। यह सिस्टम वातावरण में सल्फर डाय-ऑक्साइड (एसओ2) के उत्सर्जन को मात्रा में कटौती करता है। एसओ2 वातावरण में सैंकड़ों पार्टिकुलेट मैटैरियल का निर्माण करती है। इसका सीधा संबंध वायु प्रदूषण से है। इस सिस्टम को लगाने की अतिरिक्त लागत संयंत्र चलाने वाली कंपनी को उठानी पड़ती है। इसलिए कंपनियां इससे छूट मांग या उसके लिए लॉबींग करें, यह बात समझ में आती है। लेकिन जिस समय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारतीय शहर सबसे ऊपर आ रहे हैं, सरकार कंपनियों को ऐसी हानिकारक मांगों को मान ले, यह बात सामान्य विवेक से समझ में नहीं आती। छूट देने के लिए जो तर्क अपनाया गया है, उसे समझना और भी कठिन है। देश में 180 से ज्यादा ताप विद्युत संयंत्र हैं। इनमें से हर संयंत्र की कई इकाइयां हो सकती हैं। अनुमान के मुताबिक भारत में ऐसी 600 से अधिक इकाइयां हैं। ताजा खबर के मुताबिक इनमें से सिर्फ उन इकाइयों में एफजीडी लगाना अनिवार्य होगा, जो श्रेणी ए में आती हैं। यानी जो या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दस किलोमीटर के घेरे में हैं या फिर उन शहरों में हैं, जहां 2011 की जनगणना के मुताबिक आबादी 10 लाख से ऊपर है। इस श्रेणी में तकरौबन 11 फीसदी इकाइयां हैं। अन्य 11 प्रतिशत इकाइयां बी श्रेणी में हैं। यह श्रेणी उन स्थलों की है, जिन्हें अत्यधिक प्रदूषित समझा जाता है। इस श्रेणी वाली इकाइयां एफजीडी लगाएँ या नहीं, यह निर्णय विशेषज्ञों की एक समिति करेगी। बाकी 78 प्रतिशत इकाइयों को सी श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें एफजीडी लगाने से पूरी छूट दे दी गई है। यह फैसला इस समझ को ठेगा दिखाता है कि प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या का स्वरूप विश्वव्यापी है। उत्सर्जन चाहे कहीं भी हो, उसका प्रभाव दूर तक जाता है। इस रूप में यह निर्णय पर्यावरण की चिंता को ही ठेगा दिखाता है। आज के दौर में इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या होगी?

बौद्धिक स्वतंत्रता के दुश्मन!

जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है कि कोई भी समाज तब सर्वाधिकारवादी हो जाता है जब उसकी संस्थाएँ सिर्फ नाम की रह जाती हैं — जब शासन के ढांचे तो बने रहते हैं, पर वे वास्तविक जिम्मेदारी निभाना छोड़ देते हैं। शासक वर्ग न तो अपने कर्तव्यों को निभाता है, न ही जवाबदेही स्वीकार करता है — पर फिर भी वह या तो बल प्रयोग से, या छल-कपट से सत्ता पर काबिज बना रहता है। ऐसे में संविधान, संसद, प्रेस — सब कुछ बना रहता है, लेकिन उनमें कोई आत्मा नहीं होती। जब समाज में यह तय कर दिया जाए कि किन दो-तीन मुद्दों पर केवल एक ही "मान्य" दृष्टिकोण हो सकता है — और बाकी सब को निंदनीय या देशद्रोही कहा जाए — तब वहाँ रचनात्मकता का अंत हो जाता है। महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने एक विस्तृत लेख "द प्रिन्सिपल ऑफ लिटरेचर" 1946 में लिखा था। यह आज के लोकतांत्रिक विश्व की बौद्धिक स्थिति को समझने के लिए आश्चर्यजनक रूप से सामयिक है। विशेष कर वर्तमान भारत के लिए। यद्यपि अग्रणी लोकतांत्रिक देशों के संदर्भ में भी इतना कठोर शीर्षक किसी को अटपटा लग सकता है, कि वैसे देशों में 'लेखन पर रोक' जैसी बात का क्या मतलब!? क्यों कि लोकतंत्र की तो सब से बुनियादी विशेषता ही है — अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तब लोकतांत्रिक देशों में लेखन पर रोक कहना बेतुकी बल लागती है। पर ऑरवेल का उक्त लेख पढ़कर इस की गंभीरता, और महत्व को हर विचारवान पाठक समझ संकेगा। मुख्यतः यह सोवियत, कम्युनिस्ट समर्थक मानसिकता वाले यूरोपीय बौद्धिकों की आलोचना था, जिसे भारत में 'प्रगतिशील' बौद्धिकता या प्रगतिवाद कहने का चलन था। उस जमाने में यह बौद्धिकता पूरे लोकतांत्रिक विश्व में अत्यंत प्रभावशाली थी। जो आले चार दशक तक मजबूती से जमी रही, और अभी भी अपना प्रभाव कमोबेश रखती है। जिसे भारत में भी बखूबी देखा जा सकता है, जब कथित दक्षिणपंथी कहलाने वाले दल और बौद्धिक भी उसी प्रगतिवाद की अनेक धारणाओं और निर्णयों को पूरे आदर, विश्वास के साथ उपयोग में लाते और उस पर चलते भी हैं। प्रायः बिना जाने भी कि यह या वह धारणा मूलतः कम्युनिस्ट यानी प्रगतिवादी मूल की है। पर जिस स्थिति पर ऑरवेल ने ऊंगली रखी थी, वह आज भी उतनी ही विचारणीय है। क्यों कि उस में दी गई स्थितियों को हम आज अपने समझ घटते, होते देख सकते हैं। नीचे उसी लेख के कुछ अंशों का हिन्दी रूपान्तर है। इस में 'सर्वाधिकारवाद' और 'लेखक' के आशय में पत्रकारिता, शैक्षिक, बौद्धिक क्षेत्र में संलग्न लोगों, पाठ्य-पुस्तक लेखन, और तमाम पाठ्य सामग्रियों को भी जोड़ कर समझना चाहिए। इस लेख की चेतावनी कितनी सटीक साबित हुई, यह तब से सोवियत रूस के इतिहास और हथ से भी यह देखा जा सकता है। वहाँ साहित्य और कलात्मक रचनाधर्मिता की, चिंतन तथा सामाजिक विषयों की शिक्षा का कितना पतन हुआ, इस का संपूर्ण आकलन करना तक कठिन है। पर यह तो सामने है कि जिस रूप में उस से पचास वर्ष पहले तक, यानी सत्ता पर कम्युनिस्ट कब्जा बनने से पहले तक, असंख्य विश्व-प्रसिद्ध रचनाकार और चिंतक होते रहे, वहाँ साहित्य लेखन और सामाजिक, दार्शनिक, शैक्षिक चिंतन लगभग शून्य हो गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के सिवा सभी विषयों की सामान्य शिक्षा घोर विकृत होकर अत्यंत दरनीय हो गई। यह रूप में एक सर्वाधिकारवादी राजनीति के वर्चस्व का परिणाम था। उसी दुर्गात के संदर्भ में ऑरवेल ने अपने देश इंग्लैंड को जोड़ते हुए चेतावनी दी थी कि सर्वाधिकारवादी मानसिकता केवल सर्वाधिकारी शासन वाले देशों में ही होती। बल्कि वह ऐसे उदार लोकतांत्रिक देशों में भी तरह-तरह के रूप में फैल सकती है जिस में साहित्य, इतिहास और वर्तमान के बारे में विभिन्न बिन्दुओं पर सच्चाई को दबाने, झूठ फैलाने, कुछ मनमानी बातों,



नारों, निष्कर्षों को थोपने, तथा वास्तविक तथ्यों में हेरफेर करने, या अनेक समाचारों पर पर्दा डालने या कमतर दिखाने की प्रवृत्ति होती है। यह सब भारत में भी लंबे समय से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही वृद्धमान रूप से होता रहा है। उस के नतीजे भी वही होते गये हैं जिस की जॉर्ज ऑरवेल ने संभावना बताई थी। इसलिए उन की यह बातें रचनात्मक लेखन, पत्रकारिता और शैक्षिक जगत के संदर्भ में समान रूप से चिंतनीय हैं। नीचे दिए गए अंतिम अंश के निष्कर्ष भारत की वर्तमान बौद्धिक स्थिति पर उतने ही लागू हैं जितने अस्सी वर्ष पहले ऑरवेल ने इंग्लैंड के लिए चेतावनी रूप में दिये थे। वह चेतावनी ही हमारे लिए विशेषतः विचारणीय है। बिलकुल निम्न स्तर से ऊपर, सभी साहित्य लेखन अपने अनुभवों को दर्ज कर अपने समकालीनों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने का प्रयास है। और जहाँ तक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात है, किसी पत्रकार और सब से 'अ-राजनीतिक' रचनात्मक लेखक में अधिक अंतर नहीं है। जब पत्रकार को झूठ लिखने, या जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है वैसे समाचार दबाने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो वह स्वतंत्र नहीं है और अपनी यह स्थिति वह जानता है। किन्तु रचनात्मक लेखक भी स्वतंत्र नहीं है यदि उसे अपनी अनुभूतियों को झूठलाना पड़े, जिन अनुभूतियों को वह सही समझता है। वह अपने लेखन में वास्तविकता को विकृत कर दे सकता है, पर अपने ही मस्तिष्क की समझ को गलत प्रस्तुत नहीं कर सकता। जिस चीज को वह नापसंद करता है उस के बारे में निष्ठा से नहीं कह सकता कि वह उसे पसंद है, या जिस पर उसे विश्वास नहीं उस पर विश्वास होना नहीं कह सकता। यदि वह ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाए तो इस का एकमात्र परिणाम होगा कि उस की रचनात्मक क्षमता सूख जाएगी। वह विश्वादास्पद विषयों से दूर रहकर भी इस समस्या को हल नहीं कर सकता। विशुद्ध अ-राजनीतिक साहित्य जैसी कोई चीज नहीं होती, और हमारे युग में तो और भी नहीं, जब किसी न किसी राजनीतिक प्रकार के भय, घृणा और वफादारीयें हरेक की चेतना की सतह के निकट हैं। यहाँ तक कि केवल एक टैबू (जिस पर कहने-लिखने से बचना हो) विषय भी मस्तिष्क को दुष्प्रभावित कर सकता है, क्यों कि यह खतरा बना रहेगा कि किसी भी विषय पर स्वतंत्रता पूर्वक अवलोकन करने, लिखने में वह उस वर्जित विषय तक न पहुँच जाए। इस का निष्कर्ष यह है कि सर्वाधिकारवाद का वातावरण किसी भी प्रकार के गद्य-लेखक के लिए मारक होता है। और किसी भी सर्वाधिकारवादी समाज में यदि दो पीढ़ी से अधिक ऐसी स्थिति रही तो यह संभव है कि गद्य साहित्य, जो विगत चार सौ सालों से रहा है, वस्तुतः निश्चित रूप से समाप्त हो जाए।

सर्वाधिकारवाद किसी विश्वास, फेथ, रखने के बदले एक संगतिहीन वैचारिक प्रवृत्ति, स्कीजोफ्रेनिया, को बढ़ावा देता है। कोई समाज सर्वाधिकारवादी हो जाता है जब उस की संरचनाएँ मनमाने तौर से दिखावटी हो जाती हैं। अर्थात् जब उस का शासक वर्ग अपना काम छोड़ देता है, पर ताकत या धोखाधड़ी द्वारा सत्ता से चिपके रहने में सफल रहता है। ऐसा समाज चाहे जितने समय बना रहे पर वह न तो सहिष्णु और — या दो विषयों पर, जो प्रायः होता है — खास तरह का जड़सूत्री मतवाद, ऑर्थोडॉक्सिज, थोप दी जाए तो अच्छा लेखन बंद हो जाता है। गद्य साहित्य बुद्धिवादी युग की देन है, जब व्यक्ति की वैचारिक, भावनात्मक स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली। इस बौद्धिक स्वतंत्रता को चोट पहुँचाने से क्रमशः पत्रकार, समाजशास्त्रीय लेखक, इतिहासकार, उपन्यासकार, समालोचक, और कवि पंगु बनते हैं। उसी क्रम में। अभी तक सर्वाधिकारवाद पूरी तरह कहीं सफल नहीं हुआ है। हमारा अपना समाज (ब्रिटेन), मोटे तौर पर, अभी तक उदार है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए आप को आर्थिक दबाव और लोकमत के ताकतवर हिस्सों से लड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ किसी सीक्रेट पुलिस का दबाव नहीं है। आप लगभग कुछ भी बोल या छाप सकते हैं जब तक कि आप किनारे रह कर यह करने के लिए तैयार हों। लेकिन सब से अनिष्टकर स्थिति वह है जब जिन के लिए बौद्धिक स्वतंत्रता सब से मूल्यवान है वे ही इस के सचेत शत्रु हो जाएं। आम जनता इस विषय की ऐसे या वैसे कोई परवाह नहीं करती। आम लोग किसी मतभेद रखने वाले व्यक्ति को न सताने जाते हैं, न उसे बचाने के लिए ही कोई प्रयास करते हैं। आम लोग एक साथ इतने विवेकशील और इतने मूढ़ भी हैं कि सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोण नहीं रख सकते। बौद्धिक गरिमा पर सीधी, सचेत चोट स्वयं बौद्धिकों द्वारा की जाती है। लेकिन जो भी लेखक सर्वाधिकारवादी दृष्टिकोण अपनाता है, जो भी सच लिखने-बोलने वाले को प्रताड़ित करने और वास्तविकता की लीचापोती करने के पक्ष में दलीलें गढ़ता है, वह स्वयं लेखक के रूप में अपने को खत्म करता है। तब इस से उस के बचने का कोई उपाय नहीं। स्वतंत्र लिखने-बोलने वाले के विरुद्ध 'व्यक्तिवाद', 'आत्मकुर्सी पर रहने वाला', जैसे मानवीय कल्पनाशीलता और रचनात्मकता भी, कुछ वही है जो अपने समाज के साथ जुड़कर चलता है', आदि इस तथ्य पर पर्दा नहीं डाल सकती कि एक किंवा हुआ दिमाग बेकार हो चुका दिमाग है। जब तक स्वतःस्फूर्त लिखने बोलने की गुंजाइश न हो तब तक साहित्यिक लेखन असंभव है, बल्कि बल तो भाषा तक थपरा जाती है। भविष्य में यदि कभी मानव मस्तिष्क बिलकुल ही कुछ और हो जाए, और तब हम साहित्यिक लेखन को बौद्धिक सत्यनिष्ठा से अलग करना सीख लें तो और बात है। किन्तु आज के लिए हम जानते हैं कि मानवीय कल्पनाशीलता और रचनात्मकता भी, कुछ जंगली जानवरों की तरह ही, कैद में नहीं फलती-फूलती। कोई भी लेखक या पत्रकार जो इस से इंकार करता है — और आज सोवियत संघ की प्रशंसा करने वाले लगभग सभी विवरणों में खुले या छिपे यही चीज है — वह वास्तुतः अपने ही विनाश की माँग कर रहा है।

राज्यसभा, राज्यपालों के बाद आगे क्या!

केंद्र सरकार लंबित काम निपटाने में लगी है। संसद के मानसून सत्र से पहले कई पॉइंटिंग काम निपटाए जा रहे हैं। राज्यसभा में मनोनीत श्रेणी की चार सीटें खाली थीं, जिन पर चार लोगों का मनोनयन हो रहा है। आगे होने वाले विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिहाज से मनोनयन किया गया है। इसके तुरंत बाद दो राज्यी, हरियाणा और गोवा में नए राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नए उप राज्यपाल की नियुक्ति हुई। अगले कुछ दिन में कुछ और राज्यपालों और उप राज्यपालों की स्थिति में परिवर्तन होना है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर की चर्चा है। उसके बाद क्या? क्या उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करेंगे? मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा कई महीनों से चल रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करेंगे। लेकिन यह कब होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है। कहा जा रहा है कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल के पांच राज्यों के चुनाव के लिहाज से फेरबदल होनी है। मुश्किल यह है कि संसद



का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। उससे पहले सरकार को कई काम करने होते हैं। विधायी कामकाज की तैयारियां होती हैं तो सर्वदलीय बैठक भी होती है। इसलिए सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल में बड़ी फेरबदल के लिए बहुत कम समय बचा है। अगर सरकार में फेरबदल 21 जुलाई से पहले नहीं होता है तो मंत्री बनने की आस लगाए नेताओं को अगस्त के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा।

जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। असल में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बिहार कोटे का असंतुलन दिखता है। बिहार से किसी राजपूत सांसदों को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया है, जबकि दो भूमिहार कैबिनेट मंत्री हैं। भाजपा की दूसरी चिंता कुशवाहा वोट को लेकर है। पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट राजद और सीपीआई माले के साथ भी गया था। एनडीए के बड़े कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। बाद में उनको राज्यसभा में भेजा गया। तभी कहा जा रहा है कि कुशवाहा एक बार फिर केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर मध्य और दक्षिण बिहार के कुशवाहा वोट को साधने के लिए उनको मंत्री बनाया जाता है तो यह अनिवार्य होगा कि किसी राजपूत को भी मंत्री बनाया जाए। राजपूत नेताओं में राजीव प्रताप

रूडी, जनार्दन सिंह सिगरीवाल और राधामोहन सिंह के नाम की चर्चा है। बिहार के अलावा भाजपा का फोकस पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल से दो लोग मोदी मंत्रिमंडल में सदस्य हैं। सुकान्त मजुमदार और शांतनु ठाकुर। लेकिन दोनों राज्यमंत्री हैं। बंगाल से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। राज्य में भाजपा के 12 सांसद हैं। तभी संभव है कि वहां से किसी और को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या सुकान्त मजुमदार को प्रमोशन मिले। तमिलनाडु और केरल में भी अगले साल चुनाव है। मुश्किल यह है कि तमिलनाडु से राज्यसभा या लोकसभा में एक भी सांसद एनडीए का नहीं है। अभी तुरंत किसी को राज्यसभा भेजना भी मुमकिन नहीं है। उधर केरल में एकमात्र लोकसभा सांसद सुरेश गोपी पहले से मंत्री हैं। भाजपा ने राज्य के अपने पुराने नेता सी सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके अलावा तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी भाजपा में जाने के लिए हाथ पैर मारते दिख रहे हैं। उनके साथ भी मुश्किल है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा।

पार्टी और सरकार में एक साथ फेरबदल!

एक चर्चा यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एक साथ फेरबदल होगी। लेकिन यहाँ मुश्किल यह है कि अचानक पार्टी में बदलाव की चर्चा थम गई है। पिछले महीने एक के बाद एक आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई। ध्यान रहे 14 प्रदेशों में संगठन का चुनाव होने के बाद सारी प्रक्रिया ठहर गई थी। कई महीनों तक सब कुछ रुका रहा। अचानक प्रदेशों में संगठन चुनाव हुए तो कहा गया कि जुलाई में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी फैसला हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए देश के आधे राज्यों में संगठन चुनाव होने की अनिवार्यता पूरी हो गई है। यानी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किसी भी समय हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति बन जाने की बात कही जा रही है। पता नहीं फिर भी क्यों मामला अटक है। अगर अगले पांच दिन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा तो फिर उसके लिए भी एक महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को



लेकर एक बार फिर संशय बन गया है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर साढ़े पांच साल काम कर चुके, जबकि कार्यकाल तीन ही साल का होता है। बहरहाल, कहा जा रहा है कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संगठन में बड़ा बदलाव होगा। नए चेहरों को पार्टी महासचिव और सचिव बनाया जाएगा। हर बार की तरह यह भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्री संगठन में भेजे जाएंगे और संगठन के लोगों को सरकार में जगह मिलेगी। प्रदेशों से नए चेहरे मोदी सरकार में लाए जाएंगे।

तो मोटापा सबसे बड़ी समस्या है!

ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने देश की सारी समस्याएँ निपटा ली हैं। नौकरी और रोजगार से लेकर पढ़ाई, कमाई, दवाई के सारे इंतजाम हो गए हैं इसलिए अब सरकार लोगों का मोटापा दूर करने में लगी है। ऐसा लग रहा है कि भारत में इतनी खुशहाली आ गई है कि लोग आरामतलब हो गए हैं और मोटे होते जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से मोटापा कम करने की अपील कर रहे हैं। आप गाड़ी में बैठें तो हर एफएम रेडियो स्टेशन पर प्रधानमंत्री की अपील सुनाई देती है, जिसमें वे लोगों से अपने खाने में 10 फीसदी तेल की कटौती करने की अपील करते हैं। मोटापा कम करने की राष्ट्रीय मुहिम छिड़ी है। तभी जब खबर आई कि सरकार समोसा और जलेबी पर नजर रखेगी तो ऐसा लगा कि यह मोटापा घटाने की प्रधानमंत्री मोदी के अभियान का हिस्सा है। खबर आई थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक दुकानदारों को एक बोर्ड लगाना होगा, जिस पर उनको यह जानकारी देनी होगी कि समोसे में कितने तेल पड़ता है और जलेबी में कितनी चीनी होती है। सिगरेट और तम्बाकू की तरह सरकार मिठाई की दुकानों पर नमकीन और मोठे के नुकसान का ब्योरा लिखवाएगी। हालाँकि अब खबर आई है



कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। हालाँकि अभी इंतजार करना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जिस खबर का खंडन किया गया वह बाद में सही साबित हुई। वैसे इस खबर के बाद तुरंत चौतरफा विरोध शुरू हो गया था और लोग कहने लगे थे कि बड़े फूड चैन और बहुराष्ट्रीय ब्रांड के सामने भी इस तरह के नोटिस लिखवाए जाएँ। अगर सचमुच सरकार मोटापे को लेकर परेशान है तो सबसे पहले तो खाने पीने की मिलावटी चीजों को बंद कराना चाहिए। यह हकीकत है कि भारत में खाने की हर चीज में जानलेवा मिलावट है। जिस तेल में प्रधानमंत्री कटौती की बात कर रहे हैं उसमें भी ज्यादातर मिलावट है।



भारत और रूस बनाएंगे ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल, चीन से लेकर अमेरिका तक सारे एयर डिफेंस हो जाएंगे फेल

एजेंसी मॉस्को

ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को ताकत ऑपरेशन सिंद्घर के दौरान दुनिया देख चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस में तबाही मचा दी थी। सोचिए जिस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को आज की तारीख में गिने चुने मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं, अगर उसका हाइपरसोनिक वैरिएंट भी बन जाए तो क्या होगा? जी हां... भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत और रूस बहुत जल्द ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व महानिदेशक अतुल राणे ने रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RT से बात करते हुए कहा है कि ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट की 'इंट रखा जा रही है।' यानि इस प्रोजेक्ट को लेकर काम शुरू हो चुका है। जिसका मतलब है कि भारत अब आधिकारिक तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की रस में शामिल हो चुका है जो आने वाले कुछ सालों में दुनिया की सैन्य शक्ति को बदलकर रख देगा। यानि भारत के पास ब्रह्मोस के तीन वैरिएंट होंगे। एक ब्रह्मोस, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। ब्रह्मोस NG- जिसका निर्माण अभी चल रहा है और ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे बनाने के लिए भारत और रूस जल्द काम शुरू करने वाले हैं। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी होगी फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े कुछ थिंक टैंक मानना है कि इसकी स्पीड Mach-5 से Mach-8 तक होने वाली है। ये काफी ज्यादा स्पीड होती है और ब्रह्मोस, जो धरती से काफी चिपककर यानि लो-फ्लाइट उड़ान के लिए जाना जाता है, उसे इस रफ्तार में इंटरसेप्ट करना करीब नामुमकिन होगा। मौजूदा समय में दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, इजरायल का आयरन डोम और यहां तक की रूस का एस-500 एयर डिफेंस सिस्टम तक इसे रोक पाने में नाकाम हो सकते हैं। रिपोटर्स के मुताबिक, यह अगली पीढ़ी



की मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल दूरी पर भी हमला कर सकेगी और इसकी मारक क्षमता इसे गेम-चेंजर बना सकती है। ब्रह्मोस हाइपरसोनिक, रूस की Zircon मिसाइल से प्रेरित हो सकती है। यह परियोजना कई साल पहले शुरू हुई थी लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लागत संबंधित मुद्दों की वजह से प्रोजेक्ट रूक गया था। लेकिन अब जबकि दुनिया के कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की रस में लगे हुए हैं तो भारत भी अपना स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की शुरूआत कर रहा है। ब्रह्मोस-1 भी भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। यह मिसाइल Mach 3.5 की रफ्तार से उड़ान भरती है और इसे थल, वायु, नौसेना और पनडुब्बी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इसके 'फायर एंड फॉरगेट' और स्टील्थ फीचर्स ने भारत को एक अचूक हथियार दे दिया है। अब जो ब्रह्मोस-11

विकसित की जा रही है, वह न सिर्फ दोगुनी रफ्तार से चलेगी, बल्कि इसकी रेंज भी लगभग 1500 किमी तक होगी। इसमें स्क्रेमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो हवा से ऑक्सीजन खींचकर ज्यादा स्पीड और लंबी दूरी तक मिसाइल को उड़ान भरने की क्षमता देगा। इसके वजन को भी घटाकर लगभग 1.3 टन रखा जा रहा है, ताकि इसे हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेज से भी दागा जा सके। रिपोट में यह भी कहा गया है कि भारत एक 'मिनी ब्रह्मोस' पर भी काम कर रहा है, जो हल्की और ज्यादा पोर्टेबल होगी, खासकर इसे फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन की गई। इसका मकसद वायुसेना की मारक क्षमताओं को बढ़ाना है, जिससे Su-30 MKI, Mirage 2000, और भविष्य के तेजज मार्क-2 जैसे विमान भी हाइपरसोनिक हथियार ले जा सकें। इससे भारत को दुश्मन की डीप-इनसाइड टारगेट्स को बेहद कम समय में खत्म करने की क्षमता मिलेगी।

अमेरिका-चीन में शुरू हो सकता है नया तनाव, यूएस आर्मी ने ऑस्ट्रेलिया में किया टायफून मिसाइल सिस्टम का टेस्ट, भड़केगा ड्रैगन

एजेंसी वॉशिंगटन

अमेरिका और चीन के बीच आने वाले समय में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नया तनाव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी सेना ने ऑस्ट्रेलिया में चल रहे टैलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास में मिड-रेंज कैपेबिलिटी (टाइफून) मिसाइल सिस्टम का लाइव-फायरिंग टेस्ट किया है। यह अमेरिका के बाहर इस तरह का पहला परीक्षण है। वहीं फिलीपींस के बाद हिंद-प्रशांत क्षेत्र में टाइफून की दूसरी तैनाती है। इस क्षेत्र में चीन पहले ही अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में अमेरिका सेना का यह कदम निश्चित रूप से चीन से उसका टकराव बढ़ाएगा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर 15 जुलाई से शुरू हुआ है। इसी अभ्यास में अमेरिकी सेना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उत्तरी क्षेत्र में टाइफून का लाइव-फायरिंग परीक्षण किया। यह पहली बार है, जब इस लंबी दूरी की जहाज-डुबोने वाले मिसाइल सिस्टम का विदेशी धरती पर परीक्षण किया गया। अमेरिकी सेना ने इस टेस्ट के सफल रहने की जानकारी दी है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन नेवी (पीएलएन) की ओर से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में हालिया महीनों में आक्रामक रवैया देखने को मिला है। कुछ महीनों पहले यहां तनाव बढ़ा था, जब चीन ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास दोनों देशों को सूचना दिए बिना लाइव फायर अभ्यास किया था। इसे चीन की अपनी समुद्री सीमाओं से परे क्षमता बढ़ाने की कोशिश की तरह देखा गया। टाइफून का लाइव टेस्ट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर से चीन को जवाबी शक्ति प्रदर्शन की तरह है। अमेरिका का टाइफून को अपने किसी हिंद-प्रशांत सहयोगी देश में तैनात करना खासतौर से चीन को नाराज कर सकता है। चीन इस तरह की तैनाती को उतेजक



मानता है। अपने पड़ोस में लंबी दूरी की मिसाइल की मौजूदगी से नाराज बीजिंग इस तरह के कदम से क्षेत्र में हथियारों की होड़ शुरू होने की चेतावनी दे चुका है। ऑस्ट्रेलिया में टाइफून के लाइव परीक्षण पर चीन की नजर इसलिए भी है क्योंकि फिलीपींस में इस लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली की स्थायी तैनाती की तैयारी चल रही है। इसकी मारक क्षमता दक्षिण चीन सागर में चीनी शहरों या उसके कृत्रिम द्वीपों तक पहुंच सकती है। फिलीपींस में तैनाती के बाद ऑस्ट्रेलिया का यह परीक्षण बीजिंग की चिंताओं को और बढ़ा सकता है। टाइफून मिड-रेंज कैपेबिलिटी (एमआरसी) प्रणाली अमेरिकी सेना की मिसाइल प्रणाली है। यह लंबी दूरी तक सटीक हमले करने, खासतौर से समुद्र में जहाजों को निशाना बनाने के लिए है। टाइफून को एक बैटरी में चार लॉन्चर होते हैं। एक लॉन्चर चार मिसाइलें ले जा सकता है। ये लोड होने से पहले 16 मिसाइलों का गुण दागती है। यह लॉन्चर एम्के 41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (वीएलएफ) से लिया गया है। यह डिजाइन कई अमेरिकी युद्धपोतों पर इस्तेमाल किया गया है।

बांग्लादेश को इस्लामिक कट्टरता की दलदल में धकेल रहे यूनुस, पाकिस्तान-एर्दोगन एक्टिव, एक्सपर्ट ने बताया भारत के लिए खतरा

एजेंसी ढाका

बांग्लादेश में बीते साल से कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जून-जुलाई के महीने में शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन ढाका में किया गया। यूनुस के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की सरकार का रुख पूरी तरह बदल गया है। एक तरफ बांग्लादेश ने घर में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया है तो वहीं दुनिया में भी उसके दोस्त बदल रहे हैं। इसने भारत के भी बॉर्डर पर चिंता को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश के जानेमाने पत्रकार सलाहूद्दीन शोएब चौधरी ने इस पर बात की है कि कैसे अपने धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहचान रखने वाले बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के शासन में इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है। पिछले 11 महीनों में यूनुस सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। खासतौर से पुलिस, बॉर्डर गार्ड और कोस्ट गार्ड में 17,000 नए लोगों की भरती की है, जो कट्टर इस्लामी पृष्ठभूमि से आते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की ISI इस इस्लामीकरण में मदद कर रहे हैं तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ा रहे



हैं। चौधरी ने अपने लेख में बताया है कि यूनुस ने ऐसे लोगों को बड़े पद दे दिए हैं, जिनको जरूरी ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। वे साधारण सैल्यूट भी नहीं कर पाते, उनकी योग्यता सिर्फ उनकी कट्टरपंथ की पृष्ठभूमि है। इससे पता चलता है कि बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था में इस्लामीकरण हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के खास सहयोगी मुफ्ती फजलुल करीम कई बार ये दोहरा चुके हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की जगह इस्लामी शरिया कानून आना चाहिए। उनका कहना है कि हिंदुओं को अधिकार तभी मिलेंगे जब वे शरिया कानून का पालन करेंगे। पाकिस्तान का मोहम्मद यूनुस सरकार पर प्रभाव

किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान के अलावा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इसी महीने, 6 जुलाई को यूनुस ने अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम NGO के एक समूह की मेजबानी की। इसके बारे में यूनुस ने सोशल मीडिया पर स्पष्टतौर पर लिखा कि इस मीटिंग का मकसद मुस्लिम दुनिया को एकजुट करना है। इस मीटिंग में तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया के इस्लामी संगठन थे। तुर्की के रक्षा उद्योग सचिव ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख से मुलाकात की है। उन्होंने बांग्लादेश को तुर्की के साथ मिलकर सैन्य उपकरण बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह एर्दोगन की विचारधारा को दक्षिण एशिया में फैलाने की कोशिश है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने जताई हत्या की आशंका कहा, मुझे कुछ हुआ तो असीम मुनीर जिम्मेदार चौधरी का कहना है कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत गंभीर है। इस पर खासतौर से भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए। यूनुस इसी रास्ते पर आगे बढ़े तो बांग्लादेश एक इस्लामी देश बन सकता है। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलेगी और खासतौर भारत इससे प्रभावित होगा क्योंकि दोनों देश एक साझा संस्कृति रखते हैं।

यूक्रेन में बड़ा सियासी फेरबदल, जेलेंस्की ने ट्रंप से मिन्जरल डील करने वाली यूलिया को बनाया पीएम

एजेंसी कीव

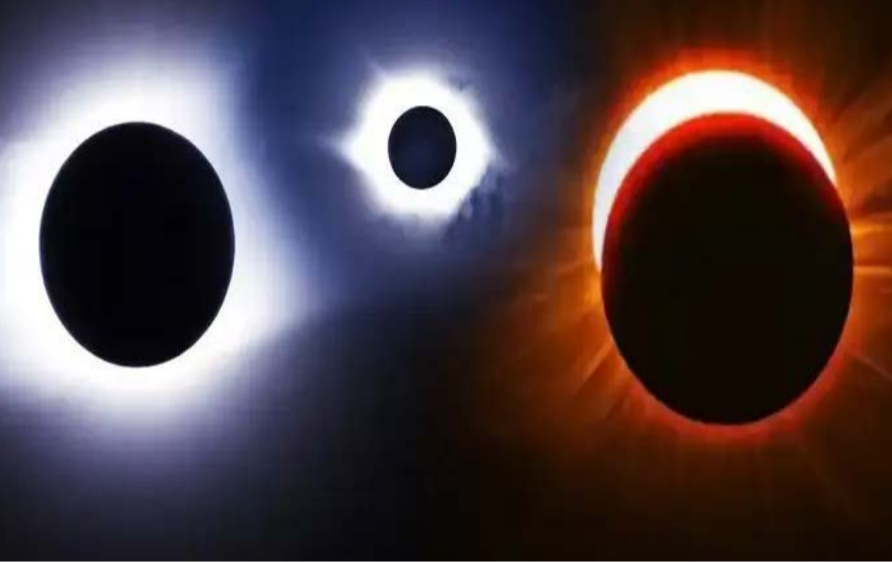
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को कैबिनेट में फेरबदल करते हुए देश के नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान किया है। वित्त मंत्री और अमेरिका के साथ मिन्जरल डील की प्रमुख वार्ताकार यूलिया स्विरिडेन्को को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह 2020 से यूक्रेन के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे डेनिस शम्यहाल का स्थान लेंगी। जेलेंस्की ने रूस के तेज होते हमलों के बीच मंत्रिमंडल में ये बड़े फेरबदल किए हैं। इसे उनकी अमेरिका से संबंधों में बेहतरी की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। जेलेंस्की ने गुरुवार को संसद में कहा कि अमेरिका के साथ नए समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे यूक्रेन का रुख मजबूत होगा। जेलेंस्की ने इस दौरान डेनिस शम्यहाल को पीएम से रक्षा मंत्री बनाने जैसे



कई फैसलों का ऐलान किया। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान प्रधानमंत्री के रूप में स्विरिडेन्को की नियुक्ति

ने खींचा है। वह ट्रंप प्रशासन साथ यूक्रेन की खनिज समझौते पर बातचीत से चर्चा में आई थीं। यूलिया स्विरिडेन्को ने रक्षा सहयोग, आर्थिक सुधार और पुनर्निर्माण पर केंद्रित पश्चिमी सहयोगियों के साथ उच्च-स्तरीय वार्ताओं में कई बार यूक्रेन का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें राष्ट्रपति जेलेंस्की की वफादार नेता के तौर पर गिना जाता है। एक और अहम बदलाव अमेरिका में नए राजदूत का नामांकन है। जेलेंस्की ने ओलगा स्ट्रेफनिशिना को वॉशिंगटन में यूक्रेन का अगला राजदूत नियुक्त करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

हजारों वर्षों से नहीं हुआ, ना अगले 100 साल में होगा... दुनिया को हैरान करेगा पूर्ण सूर्यग्रहण, 6 मिनट तक दोपहर में हो जाएगी रात



एजेंसी वॉशिंगटन

खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए आसमान में कुछ खास होने जा रहा है। ये खास घटना सूर्य ग्रहण की वजह से होगी। साल 2027 में दुनिया की ऐतिहासिक पूर्ण सूर्यग्रहण देखने को मिलेगा। इस दौरान दोपहर के वक्त आसमान अंधेरे में डूब जाएगा। यह ऐसा सूर्य ग्रहण होगा, जैसा हालिया इतिहास में कभी नहीं देखा गया और अगले करीब 100 वर्ष तक भी नहीं देखने को मिलेगा। यह सूर्य ग्रहण अटलांटिक महासागर से शुरू होकर जिब्राल्टर जलडमरूमध्य, दक्षिणी स्पेन, उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तक जाएगा। हालांकि हिंद महासागर के ऊपर यह धुंधला जाएगा। दुनिया के बड़े हिस्से को यह सूर्य ग्रहण 2 अगस्त, 2027 को देखने को मिलेगा। इस दौरान सूर्य आंखों से पूरी तरह ओझल हो जाएगा और दुनिया करीब छह मिनट के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। यह सैकड़ों वर्षों के इतिहास का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा। अभी तक इतिहास का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 743 ईसा पूर्व हुआ था, जब 7 मिनट 28 सेकंड के लिए अंधेरा छा गया था। अगस्त, 2027 में होने वाला सूर्य ग्रहण का पूर्ण पथ 275 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में यह कई महाद्वीपों को कवर करेगा। इसे महान उत्तरी अफ्रीकी ग्रहण भी कहा जा रहा है क्योंकि अफ्रीका के ज्यादातर देशों से दिखाई देगा। 2 अगस्त, 2027 के सूर्य ग्रहण अपनी अर्धधि

की वजह से विशेष होगा। यह छह मिनट चलेगा और ऐसा अगले 100 वर्षों तक नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट का कहना है कि 2027 के बाद इस तरह का सूर्य ग्रहण शायद 2114 में होगा। अगस्त, 2027 का सूर्य ग्रहण अटलांटिक महासागर में शुरू होगा और जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के पास जमीन पर उतरेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण सबसे पहले दक्षिणी स्पेन, जिब्राल्टर और मारोको में दिखाई देगा। इसके बाद अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र में सूर्य ग्रहण तब होगा, जब वह आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होगा। मिस्र के बाद सूर्य ग्रहण लाल सागर को पार करते हुए सऊदी अरब, यमन और सोमालिया में अंधेरा करेगा। स्पेन के काडिज और मलागा शहरों में चार मिनट से ज्यादा तक पूरी तरह से अंधेरा रहेगा। मोरको के टैजिगर और टेटुअन पूर्ण सूर्यग्रहण देखने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में होंगे क्योंकि ये केंद्रीय छाया पट्टी के ठीक नीचे होंगे। लीबिया का बंगाजी इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए एक अच्छा स्थान होगा। लीबिया के आसमान में पांच मिनट तक अंधेरा छाया रहेगा। मिस्र के ऐतिहासिक शहर लक्सर के पास छह मिनट तक घना अंधेरा रहेगा। इटली का लैम्बुडुसा द्वीप लगभग पूरी तरह से ढका रहेगा। सऊदी अरब के जेदा और मक्का, यमन और सोमालिया के कुछ हिस्से ग्रहण देखने वाले अंतिम स्थान होंगे। खगोल विज्ञान के इतिहास की इस बड़ी घटना को भारतीय नहीं देख सकेंगे। अगस्त, 2027 का सूर्यग्रहण भारत और



चीनी सैनिकों का LAC के पास बड़ा युद्धाभ्यास, रोबोट भेड़ियों और तोपों को उतारा, रिश्ते सामान्य करने की कोशिश सिर्फ साजिश

एजेंसी बीजिंग

1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भारतीय घरों में लगता था और फिर 1962 में हमला कर चीन, भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है। चीन के एक बार फिर से भारत के साथ संबंधों के सामान्य होने की बात कर रहा है, लेकिन उसके इधरे किसी भी तरह से रिश्तों को सामान्य करने जैसे दिख नहीं रहे हैं। चीन की सेना PLA ने भारतीय सीमा से लगते क्षेत्र में भीषण युद्धाभ्यास किया है, जिसका वीडियो देखने के बाद भारत के पूर्व फाइटर जेट पायलट और मिलिट्री एनालिस्ट विजयपन्ध के ठाकुर ने पूछा है कि 'क्या भारतीय सेना ऐसे हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है?' हाल के दिनों में PLA ने प्लएसी के पास सैन्य गतिविधियां काफी तेज कर दी हैं। ताजा अभ्यास में चीन ने न सिर्फ अपने PCL-181 हॉवित्जर तोपों का उच्च हिमालयी क्षेत्रों में टेस्ट किया है, बल्कि उसने पहली बार युद्ध के मैदान में रोबोट ड्रॉग, जिसे ग्लोबल टाइम्स ने 'रोबोट भेड़िया' कहा है, उसे ऑटोमैटिक हथियारों के साथ उतार दिया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इन रोबोट भेड़ियों का वजन करीब 70 किलोग्राम है और ये आधुनिक असॉल्ट राइफलों और रोकान पेलोड से लैस हैं। इन्हें आसानी से ऊंची जगहों पर चढ़ाने, पहाड़ी क्षेत्रों में ऑपरेट करने और सीढ़ियां पार करने वाले मिशन के लिए तैयार किया गया है। इसका मकसद साफ है की चीन भविष्य की युद्ध की तेजी से तैयारी कर रहा है। हिमालयी क्षेत्र में युद्ध काफी मुश्किल हालातों में होते हैं और जवानों के लिए ऐसे हालात में एक कठिन लड़ाई लड़ना काफी मुश्किल माना जाता है। लेकिन अगर ये रोबोट लड़ाई लड़ने लगे तो उनमें जान जाने का कोई डर नहीं रहेगा। और वो इंसानों की तुलना में कैसी भी परिस्थितियों में युद्ध लड़ सकते हैं। उनके अंदर मानवीय संवेदान नाम की कोई चीज भी नहीं होगी। जो

वीडियो सामने आए हैं उनमें देखा जा रहा है कि ये रोबोट, सैनिकों के साथ मिलकर टारगेट की पहचान कर रहे हैं, सटीक हमला कर रहे हैं और कवर फायरिंग जैसे काम कर रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया CCTV की रिपोर्ट के मुताबिक ये रोबोट अब संगठित यूनिट्स के रूप में मानव, वाहन और अन्य रोबोट्स के साथ नेटवर्क बनाकर युद्ध लड़ सकते हैं, जिससे चीन की सेना की स्पेशल ऑपरेशन और इन्फैंट्री यूनिट्स की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। हालांकि हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि इस युद्धाभ्यास को किस तारीख को किया गया है, लेकिन इसके हालिया समय में होने की रिपोर्ट है। इस युद्धाभ्यास के दौरान PLA सैनिकों ने QBZ-191 राइफल, सटीक निशानेबाजी के लिए QBU-191 और पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। वहीं, घास में छुपे ड्रोन ऑपरेटर्स ने FPV (First Person View) ड्रोन से सुसाइड हमले और निगरानी की। आपको बता दें कि FPV ड्रोन से यूक्रेन ने पिछले दिनों रूस के एयरबेस पर खतरनाक हमला करते हुए 12 से ज्यादा बॉम्ब्स एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ने रोबोट फोर्स को उतारा है, जिससे बिल्कुल ही उनकी सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि रोटोट मशीन है और इंसानों की तरह वो थकते नहीं हैं, उन्हें चोट लगने, जखमी होने या उनकी जान जाने का कोई खतरा नहीं होता। वो सीधा हमला कर सकते हैं। जिससे विरोधी खेमे के सैनिकों पर मानसिक असर होता है, क्योंकि रोबोट सैनिक लगातार आगे बढ़ते हैं और विरोधियों के गोली से बचने के लिए छिपने की कोशिश नहीं करते। यह सैन्य अभ्यास ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत LAC पर अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर सतर्क है। सवाल यह है कि क्या भारतीय सेना भविष्य के इस 'मानव-रोबोट युद्ध' के लिए तैयार है? जहां चीन एक के बाद एक तकनीकी खलांग लगा रहा है, वहीं भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि सीमा पर ऐसे खतरों से निपटने की तैयारियां तेज करे।



जिस नवजात बच्चे को गोद में खिलाया, हाथों से नहलाया, वो अब ले रहा लियोनेल मेसी की जगह

एजेंसी नई दिल्ली

स्पेन के फुटबॉलर लामिन यमाल अभी सिर्फ 18 साल के ही हैं। इसके बाद भी फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं। उन्होंने 2024 में स्पेन को यूरो चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वह स्पेन के ही क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। विंगर के रूप में खेलने वाले यमाल ने पिछले सीजन क्लब के लिए 18 गोल किए थे। बार्सिलोना ने पिछले सीजन ला लीगा के साथ ही कोपा डेल रे और स्पेनिश सुपर कप का भी खिताब जीता था। पिछले साल उन्हें गोल्डन बॉय अवॉर्ड भी मिला था। लामिन यमाल बार्सिलोना के लिए अब नंबर-10 जर्सी पहनकर खेलेंगे। मेसी 2008 से 2021 तक क्लब के लिए यह जर्सी पहनते थे। उनके जाने के बाद अंशु फेती को यह नंबर मिल गया। फेती लोन पर फ्रेंच क्लब मोनाको जा चुके हैं।

एसे में क्लब ने यमाल को 10 नंबर की जर्सी देने का फैसला किया है। मेसी से पहले बार्सिलोना के महान फुटबॉलर रोनाल्डिन्हो बार्सिलोना के लिए नंबर-10 की जर्सी पहनते थे। कुछ दिनों पहले एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही थी, जिसमें फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी एक नन्हे बच्चे के साथ नजर आ रहे हैं। यह कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि मौजूदा लामिन यमाल है। यह तस्वीर करीब 14 साल पुरानी है, जब मेसी बार्सिलोना की ओर से एक चैरिटी कैलेंडर इवेंट में हिस्सा ले रहे थे और उस समय वे सिर्फ 20 साल के थे। इस ऐतिहासिक तस्वीर को यमाल के पिता ने पिछले साल यूरो कप के दौरान सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने इसका कैप्शन दिया- 'दो दिग्गजों की शुरुआत।' फोटो खींची थी फोटोग्राफर जोन मोनफोर्ट ने, जो एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम करते हैं। यह फोटो यूनिसेफ और स्पोर्ट्स अखबार 'डायरीओ

स्पोर्ट' के संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा थी, जिसमें हर साल बार्सिलोना के खिलाड़ियों के साथ फोटोशूट के लिए स्थानीय बच्चों को चुना जाता था। मोनफोर्ट के अनुसार, यमाल के परिवार को एक लकी ड्रॉ के जरिए चुना गया था, जो मातरो शहर के पास के रोका फोंडा इलाके से आया था। इस ड्रॉ के जरिये यमाल को कैप नोड स्टेडियम में मेसी के साथ तस्वीर खिंचवाने का मौका मिला। मोनफोर्ट उस फोटोशूट को याद करते हुए बताते हैं, 'मेसी स्वभाव से शमीले और इंटीमेट थे। जब वह लॉकर रूम से बाहर आए, तो उन्हें अचानक कहा गया कि एक बच्चे को प्लास्टिक के टब में नहाते हुए पकड़ें। शुरुआत में वह थोड़े असहज थे और उन्हें यह तक नहीं समझ आ रहा था कि बच्चे को कैसे पकड़ा जाए।' उस वक्त मेसी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे। 2004 में बार्सिलोना के लिए उन्होंने डेब्यू किया था।

फिट नहीं तो मत खेलो! जसप्रीत बुमराह को लेकर अजीत अगरकर पर क्यों भड़के दिलीप वेंगसरकर

एजेंसी नई दिल्ली

इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से पिछड़ रही है। लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 22 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 23 जुलाई से शुरू हो रहे चौथे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की एक और टेशन बढ़ गई है। ये टेशन चौथे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के खेलने को लेकर है। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत यह कहा जा रहा है कि बुमराह चौथे टेस्ट मैच से बाहर रह सकते हैं। वर्कलोड के कारण ही बुमराह दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। दरअसल जसप्रीत बुमराह को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले ही कहा था कि बुमराह सभी पांच मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। ऐसे में अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज दिलीप वेंगसरकर ने चयनकर्ताओं के इस फैसले पर अपनी निराशा जताई है। खास तौर से बुमराह के निजी पसंद को लेकर उन पर सवाल



उठाए हैं। जसप्रीत बुमराह को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भारतीय खिलाड़ी दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि खिलाड़ियों को सीरीज के सभी मैच खेलने चाहिए और इसमें कोई

निजी पसंद नहीं होनी चाहिए। वेंगसरकर ने रेवस्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, 'मैं गेंदबाजों के टेस्ट मैच चुनने के पक्ष में नहीं हूँ। यदि आप फिट और उपलब्ध हैं तो आपको अपने देश के लिए सभी मैच खेलने चाहिए।' उन्होंने कहा, 'बुमराह एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं और वह भारत के लिए मैच जीत सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप दौरे पर होते हैं तो आपको हर मैच खेलना होता है। निजी पसंद के आधार पर मैच चुनने का कोई सवाल ही नहीं है। जरूरी है टीम के लिए खेलना। अगर आप अनफिट हैं तो बिल्कुल न मत खेलिए। पहले टेस्ट मैच के बाद उनके पास लगभग

7-8 दिनों का अंतर था फिर भी उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए शामिल नहीं किया गया जो स्वीकार्य नहीं था। शायद यह अगरकर और गंभीर के लिए स्वीकार्य था।'

टीम इंडिया के लिए मैजिस्ट्रल टेस्ट से पहले बुरी खबर, प्रैक्टिस के दौरान तेज गेंदबाज हुआ चोटिल



एजेंसी नई दिल्ली

भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में हार मिली। लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड ने सिर्फ 22 रनों से मुकाबला अपने नाम किया। इस हार के बाद शुभमन लिल की टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछे हो गई है। अब मैजिस्ट्रल टेस्ट से पहले उनके फिटनेस पर भी सवाल है। पंत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और सीरीज में दो शतक के साथ दो फिफ्टी लगा चुके हैं। ऐसे में चौथे टेस्ट में अश्विनी शर्मा को भी एक इंटका लगा है। ऑफ स्पिनर शोएब बशीर बाकी टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। लॉर्ड्स में तीसरे दिन रविंद्र जडेजा के एक शॉट को फिल्टरिंग करते समय उनकी बाएं हाथ की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। 21 साल के बशीर ने भारत की दूसरी पारी में सिर्फ 5.5 ओवर गेंदबाजी की। लेकिन, उन्होंने मोहम्मद सिराज का आखिरी विकेट उतारकर इंग्लैंड को यादगार जीत दिलाई। बशीर की इस सप्ताह सजरी होगी। लियाम डॉसन को बशीर के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।

भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में हार मिली। लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड ने सिर्फ 22 रनों से मुकाबला अपने नाम किया। इस हार के बाद शुभमन लिल की टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछे हो गई है। अब मैजिस्ट्रल टेस्ट से पहले उनके फिटनेस पर भी सवाल है। पंत बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और सीरीज में दो शतक के साथ दो फिफ्टी लगा चुके हैं। ऐसे में चौथे टेस्ट में अश्विनी शर्मा को भी एक इंटका लगा है। ऑफ स्पिनर शोएब बशीर बाकी टेस्ट मैचों से बाहर हो गए हैं। लॉर्ड्स में तीसरे दिन रविंद्र जडेजा के एक शॉट को फिल्टरिंग करते समय उनकी बाएं हाथ की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। 21 साल के बशीर ने भारत की दूसरी पारी में सिर्फ 5.5 ओवर गेंदबाजी की। लेकिन, उन्होंने मोहम्मद सिराज का आखिरी विकेट उतारकर इंग्लैंड को यादगार जीत दिलाई। बशीर की इस सप्ताह सजरी होगी। लियाम डॉसन को बशीर के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।

मोहम्मद सिराज के साथ अन्याय वर्कलोड मैनेजमेंट पर आकाश चोपड़ा की ये बात BCCI को चुभ जाएगी

एजेंसी नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बीसीसीआई के वर्कलोड मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से पहले मोहम्मद सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को लेकर खूब बात होती है, जिसमें बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज से पहले ही साफ कर दिया था कि वह सभी मैच नहीं खेलेंगे। आकाश चोपड़ा ने सिराज के समर्थन में कहा कि वह टेस्ट मैचों में लंबे स्पेल करते हैं, लेकिन उनके अन्य साथियों के विपरीत उनके वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में शायद ही कभी बात की जाती है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'वह बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। वह बहुत सारे ओवर फेंकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि यह सही नहीं है कि आप सबके बारे में



बात करते हैं, लेकिन उनके बारे में नहीं। हालांकि, वह अपना 100 प्रतिशत देते हैं। जब भी वह गेंदबाजी करने आते हैं तो पूरे दिल से और तेजी से दौड़कर गेंदबाजी करते हैं।' बता दें कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जब जसप्रीत बुमराह दूसरे

टेस्ट मैच में मैदान पर नहीं उतरे थे, तो मोहम्मद सिराज ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। आकाश दीप सिंह के साथ गेंदबाजी की अगुवाई करते हुए सिराज ने दूसरे टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट अपने नाम किए थे। उनके इस दमदार प्रदर्शन के कारण ही टीम इंडिया ने इस मैच में जीत हासिल की थी। वहीं, इस पूरी सीरीज की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज ने अब तक खेले तीन टेस्ट मैचों में कुल 13 विकेट हासिल किए हैं। उनका सबसे शानदार प्रदर्शन दूसरे टेस्ट मैच में रहा था। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल कर सीरीज को 1-1 से बराबर किया था, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट में मिली हार के बाद अब टीम इंडिया 2-1 से पिछड़ गई है।

व्यापार

अमेरिका-यूरोप ने लटका दी है तलवार रूस के कारण भारत की 'अग्निपरीक्षा'

एजेंसी नई दिल्ली

भारत का रूस के साथ व्यापार, खासतौर से तेल आयात, अब अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत अखरने लगा है। उन्होंने भारत पर तलवार लटका दी है। यह किसी 'अग्निपरीक्षा' से कम नहीं है। भारत पर अपनी ऑयल स्ट्रैटेजी को बदलने का भारी दबाव है। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते भारत का रूसी तेल आयात पश्चिमी देशों के बयानबाजी का केंद्र बना हुआ है। नाटो (NATO) के महासचिव मार्क रूटे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर सेंकेंडरी सैंक्शंस और भारी टैरिफ की चेतावनी दे दी है। इन धमकियों को रूस पर दबाव डालने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है ताकि वह शांति वार्ता के लिए गंभीर हो। हालांकि, भारत ने अब तक रूस से अपने तेल आयात में कटौती नहीं की है। अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को उसने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। वहीं, इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) का मानना है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए। उसे अमेरिका के दबाव को खारिज कर देना चाहिए। जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, रियायती रूसी कच्चे तेल ने ग्लोबल उथल-पुथल के बावजूद भारत को भूमिका निभाई है। उनका तर्क है कि बाहरी दबाव में अपनी नीति बदलने से अमेरिकी धमकियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि यह केवल और अधिक मांगों को दावत देगा। श्रीवास्तव ने यह भी जोड़ा कि वाशिंगटन के साथ एक व्यापार सौदा भी संरक्षण की गारंटी नहीं देगा। कारण है कि ट्रंप बाद में टारगेट बदल सकते हैं। अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध और टैरिफ की अनिश्चितताओं के बीच भारत का रूस के साथ व्यापार फिर

से पश्चिमी देशों की बातों में छाया हुआ है। ये बातें रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर ही रही हैं। NATO के सेंक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने बुधवार को कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन्हें सेंकेंडरी सैंक्शंस का बहुत बुरा असर झेलना पड़ सकता है। रूटे ने वाशिंगटन में कहा कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करके कहना चाहिए कि उन्हें शांति वार्ता को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। नहीं तो इसका ब्राजील, भारत और चीन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। कुछ हफ्ते पहले भारत में अमेरिका के एक बिल को लेकर चिंता जताई गई थी। इस बिल में रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी थी कि अगर 50 दिनों के अंदर रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौता नहीं होता है तो रूसी सामान खरीदने वालों पर 100% की दर से 'कड़े' सेंकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे। इंडस्ट्री के जानकारों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रूस से आयात करने वाले देशों पर दबाव बनाया जा सके। भारत ने अभी तक रूस से तेल का आयात कम नहीं किया है। भारत का कहना है कि वह सबसे अच्छी कीमत पर तेल खरीदने को तैयार है, बशर्त कि तेल पर कोई सैंक्शन न लगा हो। अभी रूसी तेल पर सीधे तौर पर कोई सैंक्शन नहीं है। लेकिन, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने 60 डॉलर प्रति बैरल की कीमत सीमा तय की है। इसके अनुसार, अगर रूसी तेल की कीमत इस स्तर से ऊपर जाती है तो पश्चिमी शिपर्स



भारत में अमेरिका के एक बिल को लेकर चिंता जताई गई थी। इस बिल में रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी थी कि अगर 50 दिनों के अंदर रूस-यूक्रेन के बीच शांति समझौता नहीं होता है तो रूसी सामान खरीदने वालों पर 100% की दर से 'कड़े' सेंकेंडरी टैरिफ लगाए जाएंगे। इंडस्ट्री के जानकारों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब पुतिन पर दबाव बनाने की रणनीति है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि रूस से आयात करने वाले देशों पर दबाव बनाया जा सके। भारत ने अभी तक रूस से तेल का आयात कम नहीं किया है। भारत का कहना है कि वह सबसे अच्छी कीमत पर तेल खरीदने को तैयार है, बशर्त कि तेल पर कोई सैंक्शन न लगा हो। अभी रूसी तेल पर सीधे तौर पर कोई सैंक्शन नहीं है। लेकिन, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने 60 डॉलर प्रति बैरल की कीमत सीमा तय की है। इसके अनुसार, अगर रूसी तेल की कीमत इस स्तर से ऊपर जाती है तो पश्चिमी शिपर्स

और इश्योरेंस कंपनियां रूसी तेल के व्यापार में शामिल नहीं हो सकती हैं। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक हैं। भारत सरकार अमेरिकी सांसदों और ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर रही है ताकि भारत को ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं बता सके। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88% आयात करता है। रूस लगभग तीन सालों से भारत के तेल आयात का मुख्य स्रोत रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल से किनारा कर लिया। इसके बाद रूस ने इच्छुक खरीदारों को अपने तेल पर छूट देनी शुरू कर दी। भारतीय रिफाइनर ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि रूस, जो पहले भारत को तेल की थोड़ी-बहुत सप्लाई करता था, अब भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। इसने पारंपरिक पश्चिम एशियाई सप्लायर्स को पीछे छोड़ दिया है। समय के साथ छूट में बदलाव आया है। लेकिन, पश्चिमी देशों के दबाव और रूस के तेल व्यापार पर लगे सीमित सैंक्शंस के बावजूद भारत में रूसी तेल का प्रवाह मजबूत बना हुआ है। रूस के साथ बढ़ते तेल व्यापार ने रूस को भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों की लिस्ट में भी ला दिया है। भारत का रूस से तेल का आयात जून में 11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इससे ये बात और पक्की हो गई कि नई दिल्ली के तेल आयात में रूस का दबदबा लगातार

बना हुआ है। टैंकर के आंकड़ों के अनुसार, जून में भारत के कुल तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी 43.2% थी। ये आंकड़ा अगले तीन सबसे बड़े सप्लायर्स - पश्चिम एशियाई देशों इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात - के कुल आयात से भी ज्यादा है। ग्लोबल कर्मांडो मार्केट एनालिटिक्स फर्म केप्लर के वेबल ट्रेकिंग डेटा के अनुसार, जून में भारत ने रूस से 2.08 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) कच्चे तेल का आयात किया। ये जुलाई 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। महीने-दर-महीने के आधार पर 12.2% ज्यादा है। भारत के आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में रूस से तेल का आयात 8.74 करोड़ टन था। ये भारत के कुल तेल आयात 24.4 करोड़ टन का लगभग 36% है। यूक्रेन में युद्ध से पहले भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी। 2024-25 में रूस से भारत के तेल आयात का मूल्यांकन 50 अरब डॉलर से ज्यादा था। यह भारत के कुल तेल आयात 143 अरब डॉलर का 35% है। केप्लर में रिफाइनिंग एंड मॉडलिंग के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रिंतोलिया ने कहा, 'रूसी तेल की मात्रा में ये उछाल कर्मशियल प्रोत्साहन और भू-राजनीतिक बदलावों को दर्शाता है। रूसी तेल छूट, भुगतान के तरीकों और वैकल्पिक शिपिंग और इश्योरेंस नेटवर्क के जरिए लॉजिस्टिक्स प्लेक्सिबिलिटी के कारण बहुत प्रतिस्पर्धी बना हुआ है। पश्चिमी देशों के बढ़ते सैंक्शंस के बावजूद भारतीय रिफाइनर रूस से खरीदो को बनाए रखने और यहां तक कि बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। जब तक कोई गंभीर लॉजिस्टिक्स या रेगुलेटरी रुकावट नहीं आती है, तब तक ये ट्रेंड आने वाले महीनों में भी जारी रहने की संभावना है।' इन सभी बातों को देखते हुए यह संभावना कम ही है कि भारत रूस से अपनी ऑयल इम्पोर्ट स्ट्रैटेजी में किसी तरह का बदलाव करेगा। यह भारत के हित में भी नहीं है।



अब भारत बन गया नया अरवाड़ा, चीन का ये शक्स एलन मस्क को कुचल देने पर आमादा, बैटरी बनाने का रहा है माहिर

एजेंसी नई दिल्ली

पिछले कुछ महीनों में चीन की BYD कंपनी ने पूरी दुनिया में एलन मस्क की टेस्ला को ईवी (इलेक्ट्रिक कारों) की बिक्री में पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, भारत में BYD ने पिछले महीने केवल 500 गाड़ियां ही बेचीं। टेस्ला की भारत में एंटी के साथ अब दोनों कंपनियों के लिए नया अखाड़ा बन गया है। जाने-माने इन्वेस्टर राहुल माथुर का कहना है कि मस्क और BYD के वांग चुआनफू के बीच मुकाबला अब भारत में भी देखने को मिलेगा। वचंसव की यह लड़ाई कई मायनों में बहुत अहम होगी। राहुल माथुर ने लिंकडइन पर

लिखा कि BYD ने भारत में जितनी कारें बेचीं, वो उसकी पूरी दुनिया में हुई बिक्री का लगभग 0.1% है। BYD ने पूरी दुनिया में 3.8 लाख कारें बेची हैं। भारत में BYD भले ही ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन उसकी तकनीक विदेश में काफी आगे है। चीन में BYD के नए मॉडल सिर्फ 5 मिनट में चार्ज हो जाते हैं और 500 किलोमीटर से ज्यादा चलते हैं। माथुर जिस MG ZS ईवी का इस्तेमाल करते हैं, उससे यह लगभग 50 गुना तेज है। BYD के संस्थापक और चेयरमैन वांग चुआनफू चाहते हैं कि ईवी कारों को चार्ज करना उतना ही आसान हो, जितना पेट्रोल भरवाना। अमेरिकी अरबपति निवेशक चार्ली मुंगर जब जीवित थे तो उन्होंने वांग चुआनफू की तारीफ करते हुए उन्हें थॉमस

एडिसन और जैक वेल्च का कॉम्बिनेशन बताया था। वांग चुआनफू खुद गाड़ी चलाकर ऑफिस जाते हैं। हफ्ते में 70 घंटे काम करते हैं। फेक्ट्री में कर्मचारियों के साथ रहते हैं। वांग चुआनफू पहले बैटरी बनाने का काम करते थे। उन्होंने 1995 में BYD की शुरुआत की। 2003 में BYD ने गाड़ियां बनाना शुरू किया और 2009 में अपनी पहली ईवी कार लॉन्च की। बकशायर हैथवे ने 2008 में BYD में 23 करोड़ डॉलर का निवेश किया था, जो अब 15 गुना से ज्यादा हो गया है। BYD ने 2022 में भारत में Atto 3 SUV लॉन्च की थी, जिसे चेन्नई में बनाया जा रहा है। लेकिन, मई 2025 में इसकी बिक्री के कुल ईवी बाजार का 4% से भी कम था।

जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे पर मिल नहीं रही सफलता

बाबा मठारदेव सारनी और छोटा महादेव भोपाली पर्यटन स्थल बनने की बड़ी संभावना

प्रमोद गुप्ता। सारनी

श्री श्री 1008 बाबा मठारदेव मंदिर और छोटा महादेव भोपाली पर्यटन के लिए एक बेहतर स्थल हो सकता है और इन दोनों स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी चुटियां की वजह से इन्हें सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बताया जा रहा है कि बाबा मठारदेव के शिखर मंदिर का माहौल और वर्तमान नजर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। इसके अलावा साईं मंदिर और पश्चिमी सभ्यता से निर्माण की गई श्री राम मंदिर की शैली को देखकर बाहर से आने वाले जन-सैलानी अपने आप को इस मंदिर में घंटों समय बिताने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा सन 1968 में निर्माण किया गया सतपुड़ा जल से जिसके 14 फाटक हैं और लगभग यह 2345 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है जो भी व्यक्ति पर्यटन के उद्देश्य से इस क्षेत्र में एक बार भ्रमण करता है तो जंगलों की खूबसूरती और जंगलों में जंगली जानवरों के अलावा अन्य पक्षियों के विचरण करने को देखकर अपने आप को दोबारा यहां आने से नहीं रोक पाए। यदि हम बात करें छोटा महादेव भोपाली की तो यहां पर भी प्राकृतिक सौंदर्य बाहरी पर्यटन के उद्देश्य से आने वाले टूरिज्म को अपने तर्फ आकर्षित करने की क्षमता रखता है छोटा महादेव भोपाली का झरना जो 12 माह पानी बहता रहता है उसकी

बात ही निराली है। हिल स्टेशन ऑन के हिसाब से यदि जिला प्रशासन यहां के युवाओं को क्षेत्र के पर्यटन स्थल के उद्देश्य से गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने के बाद इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करें तो निश्चित तौर से रोजगार के संसाधन भी पर्यटन के साथ उपलब्ध होंगे। **38 वर्षों से प्रिंट सोशल मीडिया पर पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की कर रहे मांग** : सतपुड़ा की घनी वादीओं में बसे बाबा मठारदेव और छोटा महादेव भोपाली में पर्यटन की संभावना बहुत है साल 1987 से क्षेत्र के अग्रणी मंसूरी के माध्यम से अखबार और सोशल मीडिया पर पर्यटन स्थल घोषित किए जाने की मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस ओर देखा और सुना नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में वन प्राणियों के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य सतपुड़ा जलाशय मोरों की संख्या जंगली भैंसों की जनसंख्या बड़ी मात्रा में है। वन संपदा वन क्षेत्र की जंगली जड़ी बूटियों और क्षेत्र की सुंदरता बाहरी क्षेत्र से आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत है। जिला प्रशासन को इस



पर पहल की जानी चाहिए आमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. योगेश पंडाप्रों के माध्यम से कई बार पर्यटन विभाग के मंत्री से मुलाकात करके ज्ञान सौंप कर छोटा महादेव भोपाली और बाबा मठारदेव को पर्यटन स्थल घोषित करवाने का प्रयास किया लेकिन किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पाई है, उन्होंने बताया कि अब क्षेत्र के लोगों को एक झूठ होकर बाबा मठारदेव और छोटा

महादेव भोपाली को पर्यटन स्थल घोषित करवाने के लिए मुहिम चलानी पड़ेगी और इस मुहिम में सभी राजनीतिक दल के नेताओं और जन प्रतिनिधियों के अलावा क्षेत्र के मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हो सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया चूर्ण समीप का सबसे अच्छा हिल स्टेशन है और यहां पर देश-विदेश के अलावा हॉलीवुड बॉलीवुड के हीरोहीरोइन भी आकर

इसकी सुंदरता और वन प्राणियों के जीवित विचरण करने का आनंद लेते रहते हैं जिससे गाइड को रोजगार का एक साधन उपलब्ध होता दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के युवाओं को अपने क्षेत्र की प्राकृतिक क्षमता सुंदरता और घूमने वाले स्थान का अवलोकन और सामाजिक ज्ञान रखना चाहिए ताकि पर्यटन क्षेत्र घोषित होने पर रोजगार के संसाधन क्षेत्र की युवाओं को मिल सके।

सांदीपनि विद्यालय में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत चौकी प्रभारी ने चार सौ विद्यार्थियों के घर घर जागरूकता अभियान का चलाने दिया संदेश



दैनिक कारखाने का सफर। सारनी

सांदीपनि विद्यालय घोड़ाडोंगरी में गुरुवार छात्रों को दोपहर प्रश्नात नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत लघु फिल्म दिखाई गई, सांदीपनि विद्यालय पहुंची घोड़ाडोंगरी चौकी प्रभारी आप्रपाली दहात, हेड कांस्टेबल रमेश टेकाम द्वारा चार सौ विद्यार्थियों को नशामुक्ति पर समझाइश, जन जागरूकता संदेश दिया वही छात्रों को घर घर जाकर नशामुक्ति अभियान चलाने को कहा, चौकी प्रभारी आप्रपाली दहात ने छात्रों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया वहीं नशीले पदार्थों का सेवन एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो व्यक्ति परिवार और समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। उन्होंने नारे के माध्यम से कहा हमारा है यही संदेश नशा मुक्त हो मध्यप्रदेश किसी भी चीज का नशा व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खतरे

में डालती है बल्कि अपराधों में वृद्धि का भी एक प्रमुख कारण है इस गंभीर समस्या से समाधान और एक स्वस्थ एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए, नशे से दूरी है जरूरी एक व्यापक नशा मुक्ति जन जागृति अभियान पूरे मध्यप्रदेश में चलाया जा रहा है उन्होंने विद्यालयीन छात्र छात्राओं को अपने आसपास नशा करने वाले व्यक्तियों को समझाइश देकर नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की अपील की वही यह अभियान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से ही सफल हो सकता है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर छात्र-छात्राओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किया, वहीं विद्यालय स्तर पर नशा मुक्ति पर जागरूकता पखवाड़ा अंतर्गत सांदीपनि विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान प्राचार्य विवेक तिवारी एवं संस्था के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

कोई घायल नहीं सिविल और सुरक्षा विभाग बड़े दुर्घटना के इंतजार सारनी के तिरुपति बालाजी वार्ड 12 में मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी की बिल्डिंग भर भर कर गिरी

दैनिक कारखाने का सफर। सारनी

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के खंडहर रूपी आवास गुरुवार को दोपहर एक बजे के लगभग भर-भर कर गिर गए यह घटना तिरुपति बालाजी वार्ड क्रमांक 12 की बताई जा रही है। जिस समय यह घटना हुई उस समय वार्ड के लोग या तो अपने घरों में खाना खा रहे थे या मजदूरी के लिए बाहर गए मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के खंडहर रूपी आवास गिरने की जानकारी वार्ड पार्षद इशरत बी पंचू खान को चलते ही मौके पर पहुंचकर मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सिविल सुरक्षा और मुख्य अभियंता को सूचना देने का काम किया गया है। वार्ड पार्षद ने बताया कि उनके कॉलोनी में जितनी भी पुरानी खंडहर रूपी बिल्डिंग है उसे गिराने के लिए नगर पालिका परिषद सारनी और मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सिविल और सुरक्षा विभाग को लिखित और मौखिक शिकायत दी गई है। उसके बाद भी कंपनी के छोटे-बड़े अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। **खंडहर रूपी मकान में कई लोग कर रहे हैं अभी भी निवास** : तिरुपति बालाजी वार्ड क्रमांक 12 के अलावा

दूसरे वार्ड में भी मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग की कंपनी की खंडहर रूपी बिल्डिंग में कई लोग निवास कर रहे हैं वर्तमान समय में लगातार रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से इन बिल्डिंगों में सिपेज हो जाने के कारण और बिल्डिंग लगभग 48 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण गिरना लाजमी है ऐसी स्थिति में यदि वह बिल्डिंग जिसमें गैर कर्मचारी एवं कर्मचारियों के रिश्तेदार निवास कर रहे हैं यदि वह बिल्डिंग गिरती है तो मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सुरक्षा और सिविल विभाग के आला अधिकारियों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। **सिविल और सुरक्षा विभाग केवल नोटिस बट्टे हैं आवास खाली नहीं करते** : मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के माध्यम से उनकी भूमि एवं उनके खंडहर रूपी आवास में निवास करने वाले गैर कर्मचारियों को नोटिस वितरण करने का काम वित्त 6 माह से किया जा रहा



है, लेकिन इन खंडहर रूपी आवास में निवास करने वाले लोगों को बाहर निकलने का काम नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से अब यह बिल्डिंग के गुरुवार गिर जाने के कारण मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के सुरक्षा और सिविल विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा होते दिखाई दे रहा है यदि ऐसी स्थिति में लगातार बारिश हुई और खंडहर रूपी आवास में जो गैर कर्मचारी निवास कर रहे हैं और वह बिल्डिंग गिरती है और उसके गिरने से कई लोगों की मौत होने की संभावना से नजर

अंदाज नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में सिविल और सुरक्षा विभाग पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा या सबसे बड़ा सवाल अभी से मुंह बकर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आखिर गैर कर्मचारियों को नोटिस बांटने के बजाय खंडहर रूपी आवासों से बाहर निकलने का काम सिविल और सुरक्षा विभाग क्यों नहीं कर रहे हैं। पत्रों का तो कहना है कि सिविल विभाग में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो खाली आवाज को गैर कर्मचारियों को किराए पर देकर मोटी रकम वसूलने का काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को क्षेत्र से बाहर

का रास्ता दिखाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। **इनका कहना है** तिरुपति बालाजी वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद बने तीन वर्ष का समय बिताने जा रहा है इस बीच में दर्जनों शिकायत सिविल और सुरक्षा विभाग के अलावा नगर पालिका को की गई लेकिन किसी ने भी खंडहर रूपी आवासों को गिराने की जरूरत नहीं उठाई यही वजह है कि गुरुवार को बिल्डिंग के गिरने से वार्ड में दहशत का माहौल बना हुआ है। **इशरत बी पंचू खान** वार्ड पार्षद तिरुपति बालाजी वार्ड 12